दैनिक
साधना एक्सप्रेस

वर्ष-4 | अंक -40 | sadhnaexpress@gmail.com | भोपाल, रविवार, 1 फरवरी 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य - 2 रुपये | www.sadhnaexpress.com

न्यूज ब्रीफ

'पंखे-कुर्सियां ले गए', तेज प्रताप यादव ने खाली किया सरकारी बंगला तो बीजेपी ने लगाए आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी | जनशक्ति जनता दल चीफ और पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है. उन्होंने पटना में 26 एम स्ट्रैंड रोड स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है.

बतौर विधायक वे इस सरकारी आवास में रहते थे. यह आवास अब बीजेपी कोटे के मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित हुआ है. लखेंद्र पासवान ने आरोप लगाया कि इस सरकारी आवास से पंखे, कुर्सियां, फर्नीचर, एयर कंडीशन, बल्ब समेत कई सरकारी सामान गायब हैं.

बीजेपी के मंत्री लखेंद्र पासवान ने तेज प्रताप यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगला खंडहर बन चुका है. शनिवार (31 जनवरी) को बंगले में घुसते ही उन्होंने कई आरोप लगा दिए. वहीं बंगले को लेकर विवाद शुरू हो गया है.

मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि बंगले की हालत इतनी खराबी है कि यहां रह पाना मुश्किल है. खंडहर है. छत क्षतिग्रस्त है. बंगला जर्जर है. लखेंद्र पासवान ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता की सेवा के लिए जो फर्नीचर और सुविधाएं दी जाती हैं, वह सभी सरकारी संपत्ति होती हैं जिन्हें आवास खाली करते समय यथास्थान छोड़ना होता है.

लखेंद्र पासवान ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पूर्व विधायक तेज प्रताप द्वारा इन सुविधाओं की मांग की गई थी, तो सामान अब कहां गए. यह सवाल तेज प्रताप यादव से पूछे जाना चाहिए. मंत्री के अनुसार उन्होंने भवन निर्माण विभाग को इसकी जानकारी दी है. जिसकी जांच की जाएगी.

सीएम स्टालिन का बड़ा बयान- डीएमके सरकार सिर्फ वादे नहीं करती, उन्हें पूरा भी करती है

नई दिल्ली, एजेंसी | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को शिवगंगा की समृद्ध तमिल सभ्यता, वीरता और बलिदान की विरासत को याद करते हुए कहा कि यह जिला प्रतिरोध, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कीलाडी पुरातात्विक खोजों का हवाला देते हुए कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि हजारों वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में तमिल सभ्यता फली-फूली थी।

मुथु वदुगनाथ थेवर, वेलू नाचियार, वेल्लाची नाचियार, मरुथु बंधुओं और क्रांतिकारी कुयिली सहित स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके बलिदान आज भी तमिल समाज को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि शिवगंगा वह भूमि है जिसने बलिदान को शक्ति में परिवर्तित किया।

अपनी यात्रा के दौरान, स्टालिन ने कुल 2,560 करोड़ रुपये की 49 पूर्ण परियोजनाओं और 13.36 करोड़ रुपये की 28 नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा, उन्होंने 15,453 लाभार्थियों को 205 करोड़ रुपये की कल्याणकारी सहायता वितरित की।

उन्होंने कनाडुकथन स्थित चेत्तिनाड कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान तथा कराईकुडी तालुक के कझानिवासल स्थित सरकारी विधि महाविद्यालय में 100 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए भवनों का उद्घाटन किया, जिनमें 1,300 छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इसरो-नासा की तीसरी आंख का कमाल, निसार ने बादलों को चीरकर ली तस्वीर

निसार नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसएआर) का एक संयुक्त मिशन है, जो पृथ्वी विज्ञान और उपग्रह अनुसंधान में अमेरिका-भारत के दीर्घकालिक सहयोग को दर्शाता है।

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | नासा ने बताया कि अमेरिका-भारत के एनआईएसएआर पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह से प्राप्त उच्च-रिज़ॉल्यूशन रडार छवि ने दक्षिणपूर्वी लुइसियाना में मिसिसिपी नदी डेल्टा क्षेत्र को कैद किया है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे जटिल भू-भागों में से एक में शहरी क्षेत्रों, आर्द्रभूमि, जंगलों और कृषि भूमि के सूक्ष्म विवरण सामने आए हैं। निसार नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसएआर) का एक संयुक्त मिशन है, जो पृथ्वी विज्ञान और उपग्रह अनुसंधान में अमेरिका-भारत के दीर्घकालिक सहयोग को दर्शाता है। छवि की स्पष्टता इतनी है कि इसमें लेक पोंटचार्ट्रेन कॉज़वे को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, जो केंद्र के ठीक दाईं ओर दिखाई दे रहा है। ये दोनों पुल लगभग 24 मील, या 39 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो इन्हें जल के ऊपर बना विश्व का सबसे लंबा निरंतर पुल बनाते हैं।

एल बैंड माइक्रोवेव तरंगों पर काम करता है निसार सैट

निसार में इस्तेमाल । बैड रेडार माइक्रोवेव तरंगों पर काम करता है। करीब 24 सेंटीमीटर की तरंगें बादलो को बिना किसी रुकावट के पार करती है और नीचे मौजूद जमीन, पेड़ो, इमारतों और पानी की सतह से टकराकर वापस सैटलाइट तक पहुंचती है। इसी डेटा से रंगीन और सटीक नक्शे तैयार होते हैं। निसार को 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था।

डिजास्टर मैनेजमेंट, खेती, जंगलों की निगरानी में कारगर

नासा का कहना है कि निसार का डेटा आपदा प्रबंधन, खेती, जगलो और वेटलैड्स की सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति पर नजर रखने में बेहद मददगार होगा। इसका डेटा वैज्ञानिकों और नीति-निर्माताओं के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। यह सैटलाइट हर 12 दिन में दो बार धरती की जमीन, पर्वतों और बर्फीले इलाको की निगरानी करता है।

सुनेत्रा पवार को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- अजितदादा का सपना पूरा करेंगी

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुंबई में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बधाई दी। एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वह राज्य की जनता के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और अजीत पवार के सपनों को साकार करेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि सुनेत्रा पवार जी को महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने पर हार्दिक शुभकामनाएं। वह इस जिम्मेदारी को संभालने वाली पहली महिला हैं। मुझे विश्वास है कि वह राज्य की जनता के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और दिवंगत अजीतदादा पवार के सपनों को साकार करेंगी।

महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में सुनेत्रा पवार को पद की शपथ दिलाई। 28 जनवरी को बारामती में विमान दुर्घटना में अजीत पवार के असामयिक निधन के बाद उपमुख्यमंत्री का पद रिक्त हो गया था। इसके साथ ही, सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बन गई हैं। अजित पवार का निधन उस समय हुआ जब उन्हें ले जा रहा चार्टर्ड विमान बारामती में दुर्घटनाग्रस्त होकर आग की लपटों में घिर गया। मृतकों में उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, एक फ्लाइट अटेंडेंट और दो पायलट शामिल थे।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल और वरिष्ठ एनसीपी नेता एवं मंत्री छगन भुजबल भी उपस्थित थे। सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एनसीपी नेताओं ने 'अजित दादा अमर रहे' और 'भारत मत की जय' के नारे लगाए। आज सुबह उन्हें एनसीपी विधायक दल की नेता चुना गया। सुनेत्रा पवार सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जानी जाती हैं।

पश्चिम बंगाल से अमित शाह का ममता को चैलेंज, टीएमसी के कुशासन और तुष्टीकरण का अंत होगा

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि 'मां, माटी, मानुष' का नारा, जिसके तहत वे सत्ता में आई थीं, अब अर्थहीन हो गया है क्योंकि राज्य में तीनों ही असुरक्षित हैं। उत्तर 24 परगना में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था, उनके गुट और घुसपैठियों द्वारा की जा रही जबरन वसूली और दमनकारी नियंत्रण, और राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनावी निष्पक्षता पर इसके प्रभाव को लेकर ममता सरकार की आलोचना की।

अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी की सरकार के राज्य में, जो 'मां, माटी, मानुष' के नारे के साथ सत्ता में आई थी, आज तीनों ही - मां, माटी और मानुष - असुरक्षित हैं। मां असुरक्षित है; महिलाओं की सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी नहीं है। मानुष ममता के गुट से परेशान है, और माटी घुसपैठियों के चंगुल में फंस गई है। रामायण से तुलना करते हुए शाह ने कहा कि जिस प्रकार रावण स्वयं को अजेय समझता था, उसी प्रकार बनर्जी को भी हार के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा का वोट शेयर 50 प्रतिशत से अधिक होगा और पार्टी भारी बहुमत से अगली सरकार बनाएगी।

अमित शाह ने कहा कि जब भगवान श्री राम ने रामसेतु बनाया था, तब रावण ने भी यही सोचा था कि इस धरती पर मुझे कौन हरा सकता है? ममता जी, इस बार सावधान हो जाइए, भाजपा का वोट शेयर अब 50 प्रतिशत से अधिक होने वाला है और हमारी सरकार भारी बहुमत से बनेगी। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर अमित शाह ने कहा कि एक ओर सरकार ने इस पर्व को मनाने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के स्वार्थ में वंदे मातरम का विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि बंगाल की पहचान और भारत के गौरव का विरोध कर रही हैं।

हॉफ एनकाउंटर केस को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उप्र पुलिस को लगाई जबरदस्त फटकार, कहा- 'दंड अदालत देगी, पुलिस नहीं'

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले से उत्तर प्रदेश पुलिस के पूरे तंत्र को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे यह आदेश केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की पुलिस व्यवस्था के लिए चेतावनी वाली घंटी है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल की एकल पीठ ने पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त को गंभीर चोट पहुंचने के मामलों में छह सूत्रीय सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो जिला पुलिस प्रमुखों पर अवमानना की सीधी तलवार लटकेगी।

यह फैसला उस समय आया है जब उत्तर प्रदेश में तथाकथित आधी मुठभेड़ यानि हॉफ एनकाउंटर का चलन पुलिस की पहचान बनता जा रहा था। न्यायालय ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रशंसा, पदोन्नति या सामाजिक माध्यम पर वाहवाही के लालच में किसी भी पुलिस अधिकारी को न्यायपालिका की भूमिका निभाने की छूट नहीं दी जा सकती।

हम आपको बता दें कि न्यायालय ने अपने आदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कई मामलों में पुलिस अधिकारी बिना किसी वास्तविक आवश्यकता के आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हैं और अभियुक्त के घुटने के नीचे गोली मार कर उसे अपाहिज बना देते हैं।

अरुणाचल प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि! डोनी पोलो हवाई अड्डे को मिला उड़ान योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | पूर्वोत्तर भारत के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में हो रहे बदलावों को एक बड़ी पहचान मिली है। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डे को केंद्र सरकार की क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना 'उड़ान' के तहत देश का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है।

'विंग्स इंडिया 2026' में मिला सम्मान - यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित नागरिक उड्डयन के सबसे बड़े कार्यक्रम 'विंग्स इंडिया 2026' के दौरान दिया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने यह सम्मान हवाई अड्डे के अधिकारियों को सौंपा। डोनी पोलो हवाई अड्डे को यह पुरस्कार 'आरसीएस-उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हैदराबाद में आयोजित 'विंग्स इंडिया 2026' कार्यक्रम में दिया। हवाई अड्डे को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के तहत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि यह पहचान ''क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूरे अरुणाचल प्रदेश में विकास, पर्यटन और अवसरों के लिए नए रास्ते खोलने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता'' को दिखाती है।

रविवार की छुट्टी कैंसिल! आज बजट के साथ खुलेगा शेयर बाजार, नोट कर लें कब से कब तक होगा कारोबार

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली, एजेंसी | 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। यह रविवार का दिन है। आमतौर पर शेयर बाजार में शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन कल का रविवार निवेशकों के लिए सामान्य छुट्टी के दिनों से अलग है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट भाषण को देखते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एलान किया है कि इस दौरान शेयर बाजार खुले रहेंगे और सामान्य दिनों की तरह कारोबार होगा। ऐसे में अगर आप भ्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट भाषण के दौरान कल ट्रेडिंग करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

एनएसई और बीएसई की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, बजट की अहमियत को देखते हुए 1 फरवरी को 'विशेष लाइव ट्रेडिंग सत्र' आयोजित किया जा रहा है। एक्सचेंजों का कहना है कि बजट में होने वाली बड़ी नीतिगत घोषणाओं पर बाजार को तत्काल प्रतिक्रिया देने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए रविवार होने के बावजूद बाजार बंद नहीं रहेगा। आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले केवल एक बार रविवार को भी शेयर बाजार में कारोबार हुआ था। 28 फरवरी 1999 को जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय रविवार के दिन भी घरेलू शेयर बाजार में कारोबार हुआ था।

ट्रेडिंग का समयः सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक - निवेशकों के मन में टाइमिंग को लेकर कोई कन्फ्यूजन न रहे, इसके लिए एक्सचेंजों ने स्थिति साफ कर दी है। कल बाजार की समय सारिणी सामान्य कारोबारी दिनों जैसी ही रहेगीः प्री-ओपन मार्केटः सुबह 9:00 बजे शुरू होकर 9:08 बजे तक चलेगा।

नॉर्मल मार्केटः सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर दोपहर 3:30 बजे तक नियमित कारोबार होगा।

इसका मतलब है कि आपको बजट भाषण के दौरान और उसके बाद अपनी रणनीति बनाने और सौदे करने का पूरा वक्त मिलेगा।

पीएम मोदी की अरब लीग से मुलाकात, बोले- अटूट भाईचारे से साझेदारी नई ऊंचाइयों पर जाएगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब लीग के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर भारत-अरब साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने अरब जगत को भारत का 'विस्तारित पड़ोस' बताते हुए शांति और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में अरब लीग के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बढ़ा हुआ सहयोग साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने अरब जगत को भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा बताया, जो अटूट भाईचारे के संबंधों और शांति एवं स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। आज अरब लीग के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरब जगत भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है, जो गहरे सभ्यतागत बंधनों, जीवंत जन-संबंधों और अटूट भाईचारे के संबंधों के साथ-साथ शांति, प्रगति और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, व्यापार और नवाचार में बढ़ा हुआ सहयोग नए अवसरों को खोलेगा और साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

भारत-अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक के लिए प्रतिनिधिमंडल भारत में है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अरब जगत के बीच गहरे और ऐतिहासिक जन-संबंधों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने वर्षों से हमारे संबंधों को प्रेरित और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले वर्षों में भारत-अरब साझेदारी के लिए अपने दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की और दोनों देशों के आपसी लाभ के लिए व्यापार और निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया और गाजा शांति योजना सहित चल रहे शांति प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता प्राप्त करने के प्रयासों में अरब लीग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया।

नरसिंहपुर जाते समय, गौरझामर में सक्रिय युवा सहयोगी गोविंद सिंह पटेल के पेट्रोल पंप पर कुछ समय बिताया,युवाओं का जोश और उत्साह देखकर दिनभर की थकान कम हो गई ।सभी का आभार ।@grps_lodhi

रुद्राक्ष धाम मंदिर प्रांगण में पं प्रेमभूषण के श्रीमुख से श्रीराम कथा का आयोजन आज से, मुख्य यजमान पूर्व गृहमंत्री खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह

• सागर, प्रतिनिधि

महेंद्र पाण्डेय जिला संवाददाता सागर। रुद्राक्ष धाम मंदिर प्रांगण में श्रीराम कथा एवं प्राण-प्रतिष्ठा के सात दिवसीय महाआयोजन का भव्य शुभारंभ आज 31 जनवरी को दोपहर दो बजे श्रीराम कथा के निष्णात और प्रसिद्ध विद्वान पं प्रेमभूषण जी महाराज के सानिंध्य में होगा। इस आयोजन के मुख्य यजमान पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक श्री भूपेन्द्र सिंह ने व्यवस्था से जुड़े सभी सेवादारों की संयुक्त बैठक लेकर इंतजामों की बारीकी से समीक्षा की। आयोजन के लिए रुद्राक्ष धाम मंदिर परिसर और इसके सामने स्टेडियम स्थित विशाल पंडाल समेत संपूर्ण आयोजन स्थल अयोध्या जी की तरह सजाया गया है।

पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक श्री भूपेन्द्र सिंह ने तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि इस आयोजन के लिए हम सभी ने डेढ़ माह से परिश्रम किया है। अब आगामी सात दिन हम सभी की परीक्षा का समय होगा जिसमें हम सभी को बिना किसी त्रुटि के सफल होना है। आयोजन में प्रतिदिन आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुविधा से रुद्राक्ष धाम प्रांगण में नवनिर्मित श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी मंदिर, श्रीराधा कृष्ण जी मंदिर एवं श्री राम जानकी मंदिर के सुविधाजनक दर्शन हो जाएं, सभी श्रद्धालु मनोयोग से भगवान श्री राम की कथा का श्रवण कर भक्तिभाव में डूबें और प्रसादी ग्रहण कर सकें यही सारी व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन निर्विघ्न और सफल हो इसके लिए भगवान ने ही हम सभी को निमित्त बना कर सेवा का यह अवसर दिया है जिसमें हम सभी को समर्पित भाव से काम में जुटना है।

करियर मेले से संवरते सपने : जमुनिया-चिखली विद्यालय ने छात्र-छात्राओं को दिखाई उज्ज्वल भविष्य की राह

• सागर, प्रतिनिधि

सागर | मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग व माननीय कलेक्टर महोदय श्री संदीप जी आर के निर्देशानुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनिया-चिखली में आयोजित करियर काउंसलिंग मेले ने शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तकों की सीमाओं से बाहर निकालते हुए उसे भविष्य निर्माण का सशक्त माध्यम बना दिया। यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए संभावनाओं का ऐसा द्वार सिद्ध हुआ, जहां मार्गदर्शन, प्रेरणा और अवसर तीनों का सुंदर समन्वय देखने को मिला।

कार्यक्रम में बीकेपी कॉलेज के संचालक, ख्यात शिक्षाविद एवं समाजसेवी डॉ० श्री अवनीश मिश्रा मुख्य अतिथि रहे, जबकि बीकेपी कॉलेज के व्याख्याता श्री शिवम शर्मा एवं डॉ० आन्या शरण विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।

मुख्य वक्ता के रूप में डॉ० मिश्रा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विकसित भारत 2047 के स्वप्न से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को बताया कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत प्रगति का माध्यम नहीं,

बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण का आधार भी है। उन्होंने इंजीनियरिंग, एमबीबीएस और आईटीईपी जैसे प्रमुख पाठ्यक्रमों के साथ नीट, आईआईटी, आईआईएम, जेईई, क्लैट और सीयूईटी जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की जानकारी दी। साथ ही टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग जैसे लघु डिप्लोमा एवं प्रोफेशनल कोर्सों की उपयोगिता और उनमें निहित व्यापक संभावनाओं पर प्रकाश डाला। एनडीए और सीडीएस के माध्यम से सशस्त्र बलों में करियर के अवसरों का उल्लेख करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को सेवा, साहस और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

डॉ० मिश्रा ने बच्चों की जिज्ञासाओं को धैर्यपूर्वक सुनकर उनके प्रश्नों का समाधान किया और स्पष्ट किया कि करियर केवल अच्छी नौकरी पाने तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य एक संवेदनशील, जागरूक और जिम्मेदार इंसान बनना भी है। उन्होंने कहा कि शिक्षित और संस्कारित युवा ही एक स्वस्थ, समरस और सशक्त समाज की नींव रखते हैं।

श्री शिवम शर्मा ने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए ऐसा भविष्य चुनने का संदेश दिया, जिसमें उनकी वास्तविक रुचि और लगन हो। उन्होंने कहा कि सही करियर वही है, जो दिनभर के परिश्रम के बाद थकान नहीं, बल्कि संतुष्टि का भाव दे। जीवन के इस निर्णायक पड़ाव पर बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने अनुशासन और निरंतरता को सफलता का मूल मंत्र बताया। शिवम् शर्मा ने काव्यात्मक ढंग से बच्चों में हर्ष और उत्साह की उमंग दौड़ाते हुए खूब तालियां बटोरीं। डॉ० आन्या शरण ने अपनी सहज और प्रभावी शैली में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में उपलब्ध करियर अवसरों की जानकारी दी। इसी क्रम में विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के नेत्र परीक्षण का आयोजन भी किया गया, जहां अतिथियों के हाथों निःशुल्क चश्मों का वितरण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गोबिंद बर्दिया, अजय गुप्ता सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक उपयोगी बना दिया।

सभी अतिथियों और वक्ताओं ने विद्यालय की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि जमुनिया-चिखली का यह विद्यालय पूरे क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। सीमित संसाधनों के बावजूद यहां के शिक्षकों की लगन, परिश्रम, नवाचार और अनुशासन वास्तव में अनुकरणीय हैं।

प्राचार्य श्री भरत सिंह परिहार के नेतृत्व, वरिष्ठ शिक्षक श्री अरुण कुमार दुबे के मार्गदर्शन और संपूर्ण शाला परिवार के समर्पित सहयोग ने इस संस्थान को उत्कृष्टता का प्रतीक बना दिया है। करियर मेला केवल एक कार्यक्रम भर नहीं रहा यह विद्यार्थियों के मन में लक्ष्यबद्धता का दीप जलाकर उन्हें अपने सपनों को आकार देने का साहस दे गया। निस्संदेह, ऐसे आयोजन शिक्षा को अर्थपूर्ण बनाते हैं और आने वाली पीढ़ी को आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं।

वरिष्ठ शिक्षक श्री अरुण दुबे द्वारा कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न जानकारियां प्रदान की गईं। संस्था की शिक्षिका कुमारी अंजली दांगी, श्रद्धा जैन एवं वंदना शुक्ला द्वारा भी करियर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

कार्यक्रम का संचालन श्री मोहित वैध व नरेश यादव द्वारा किया गया। शाला प्राचार्य श्री भरत सिंह परिहार जी ने इस सफल कार्यक्रम हेतु सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही आज मद्य निषेध दिवस के रूप में श्री संजय तिवारी एवं इंद्रपाल लोधी द्वारा छात्रों को शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में डॉ अरविंद यादव, डॉ राहुल चौरसिया, अंकित सोनी, कीरत सिंह, नितेश सेन एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे।

बुआ पहुंची एसपी के पास, शिकायत कर कहा- बदनाम कर रही किन्नर रानी, समाज से बाहर किया

सागर की किन्नर नायक किरण बुआ ने एसपी कार्यालय में रानी ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. किरण बुआ का आरोप है कि रानी ठाकुर उन्हें बदनाम कर रही हैं और झूठे आरोप लगा रही हैं. समाज ने रानी ठाकुर को निष्कासित कर दिया है.

• सागर, प्रतिनिधि

सागर | बुआ पहुंची SP के पास, शिकायत कर कहा- बदनाम कर रही किन्नर रानी, समाज से बाहर किया

मध्य प्रदेश के सागर शहर में किन्नर समाज के आंतरिक विवाद में नया मोड़ सामने आया है. किन्नर नायक किरण बुआ ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर किन्नर रानी ठाकुर के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया कि किन्नर रानी ठाकुर द्वेष भावना के चलते उन्हें लगातार बदनाम कर रही हैं, उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उनका नाम कथित रूप से मुस्लिम नाम से जोड़ा जा रहा है, जबकि वे स्वयं एक हिंदू परिवार से आती हैं.

बधाई राशि नहीं दिया जाएगा

किरण बुआ ने बताया कि किन्नर समाज की बैठक में रानी ठाकुर के व्यवहार को समाज विरोधी मानते हुए उसे किन्नर समाज से निष्कासित कर दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि निष्कासन के बाद रानी ठाकुर को समाज की ओर से किसी भी प्रकार की बधाई राशि या सहयोग न देने का निर्णय लिया गया है.

पुलिस कर रही जांच

एसपी कार्यालय में दी गई शिकायत में किरण बुआ ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी सामने आएगा, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बुंदेलखंड की धरती पर उग रही विदेशी सब्जियां

खिमलासा गांव का किसान बना नई खेती की मिसाल, मेडिकल का बिजनेस छोड़ महीने के लाखों कमा रहा किसान

• सागर, प्रतिनिधि

सागर | बुंदेलखंड क्षेत्र जहां पारंपरिक खेती और मौसम की मार से जूझते किसान अक्सर नुकसान का सामना करते हैं, वहीं सागर जिले की खुरई तहसील के छोटे से गांव खिमलासा के किसान अमित जैन ने आधुनिक सोच और नई तकनीक के जरिए खेती को लाभ का व्यवसाय बनाकर एक नई मिसाल पेश की है। सात एकड़ में विकसित अपने एक्वेटिक वेजिटेबल फार्म के माध्यम से अमित जैन न सिर्फ आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।

खिमलासा निवासी 43 वर्षीय अमित जैन ने पारंपरिक खेती से हटकर एक्वेटिक कृषि को अपनाया। वे बी.कॉम तक शिक्षित हैं और पहले मेडिकल शॉप का संचालन करते थे। वर्ष 2012 में पिता के निधन के बाद परिवार की खेती की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। पिता की इच्छा थी कि बेटा खेती करे, लेकिन कुछ अलग और नया करे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अमित ने खेती में नवाचार का रास्ता चुना।

खेती संभालने के बाद अमित जैन ने शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी जुटाई और उद्यानिकी विभाग, सागर से आधुनिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने एक्वेटिक पद्धति से ब्रोकली, रेड कैबेज, चाइना कैबेज, लेट्यूस सहित कई उन्नत और विदेशी किस्म की सब्जियों की खेती शुरू की। शुरुआत में जोखिम जरूर था, लेकिन मेहनत और सही तकनीक के चलते उन्हें उम्मीद से कहीं बेहतर परिणाम मिले।

अमित जैन बताते हैं कि उनकी उगाई गई सब्जियां केवल सागर जिले तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भोपाल, इंदौर और दिल्ली तक सप्लाई की जाती हैं। खासतौर पर दिल्ली की मंडियों और फाइव स्टार होटलों में इन सब्जियों की काफी मांग है, जहां इनके दाम 50 रुपये प्रति किलो से ऊपर मिलते हैं। कई बार ऑर्डर इतने अधिक हो जाते हैं कि वे सभी मॉल और होटलों की मांग पूरी नहीं कर पाते।

एक्वेटिक सब्जियों की खेती से अमित जैन सालाना एक लाख रुपये से अधिक की आमदनी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह खेती पारंपरिक फसलों की तुलना में कम पानी में अधिक उत्पादन देती है और बदलते मौसम का असर भी अपेक्षाकृत कम पड़ता है। यही कारण है कि यह पद्धति बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है।

अमित जैन की तीन बेटियां हैं, जो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। पिता की मेहनत और खेती के प्रति समर्पण को देखकर वे भी छुट्टियों और खाली समय में छोटे-मोटे कृषि कार्यों में सहयोग करती हैं। अमित मानते हैं कि बच्चों को खेती से जोड़ना भविष्य के लिए बेहद जरूरी है।

आज अमित जैन न केवल खुद आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि आसपास के किसानों को भी आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। उद्यानिकी विभाग से उन्हें इरिगेशन सिस्टम, पैक हाउस निर्माण और बर्मी कंपोस्ट के लिए सब्सिडी भी मिली, जिससे लागत कम हुई और मुनाफा बढ़ा। खिमलासा का यह किसान साबित कर रहा है कि सही जानकारी, प्रशिक्षण और नई सोच के साथ खेती को भी सफल और लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी शासकीय कार्यालयों में मौन धारण किया गया

• सागर, प्रतिनिधि

सागर | भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में दो मिनट का मौन धारण किया गया। कलेक्टर कार्यालय में भी प्रतिवर्ष की भांति इस दिन विशेष रूप से शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया। मौन धारण के दौरान सभी अधिकारी, कर्मचारी और उपस्थितजन खड़े होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कलेक्टर ने छात्र-छात्राओं के मलखंभ खेल कौशल को सराहा, पढ़ाई के साथ खेलों में रुचि लेने हेतु किया मार्गदर्शित

• सागर, प्रतिनिधि

सागर | कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने शाहगढ़ स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक खेल मलखंभ के प्रदर्शन का उन्होंने अवलोकन किया। विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट संतुलन, शारीरिक सामर्थ्य और अनुशासन का परिचय देते हुए अपने खेल कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने छात्र-छात्राओं के मलखंभ कौशल की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भागीदारी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं। वर्तमान में अच्छा करियर बनाने के लिए खेल का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा भविष्य में जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

वन के साथ जो आनंद है, वह कहीं और नहीं

वानिकी सम्मेलन और आईएफएस मीट के शुभारंभ अवसर पर सीएम ने कहा...

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित भारतीय वन सेवा मीट को संबोधित करते हुए कहा कि वन के साथ जो आनंद और अनुभूति जुड़ी है, वह किसी और क्षेत्र में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जल से जंगल और जंगल से जीवन जुड़ा है, इसे समझने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जंगल, जल और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। उन्होंने वन अधिकारियों को एक अनुभव साझा करते हुए बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जब वे वाहन से यात्रा कर रहे थे, तब टाइगर अपने स्वाभाविक अंदाज में चल रहा था। यह दृश्य वन्यजीवों की स्वतंत्रता और प्रकृति के संतुलन को दशार्ता है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने आगे कहा कि वन क्षेत्रों में काम करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि जानवरों के सामने जाना साहस और समझ दोनों की मांग करता है। निडरता और निर्भरता दोनों ही मानव और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि जानवर अपनी जिंदगी की मस्ती का आनंद लेते हैं और हम अपने जीवन का। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करियर ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि चीता हो या टाइगर, सभी वन्यजीवों का संरक्षण विभाग की प्राथमिकता है। नर्मदा में मगरमच्छों को छोड़े जाने का निर्णय चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जब विभाग बेहतर तरीके से कार्य करता है, तो मगरमच्छ नर्मदा की धारा में और घडियाल

चंबल में सुरक्षित रहते हैं। जंगल की शोभा बढ़ा रहे है मप्र के टाइगर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल की शोभा जल-जीवन से है और जंगल की शोभा उसमें विचरण करने वाले टाइगर जैसे वन्यजीवों से है। उन्होंने यह भी कहा कि आज आईएफएस अधिकारियों के साथ निचला अमला भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहा है, जो वन संरक्षण की सफलता की नींव है। मुख्यमंत्री ने कसा तंज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आईएफएस सर्विस मीट में मगरमच्छों को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि वैसे तो मगरमच्छों को पकडने की बात होती है, छोडने पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से मगरमच्छों को छोडने का मामला तो कुछ मुश्किल लगा। यहां मगरमच्छों को छोडना पकडया होता रहता है। उन्होंने प्रदेश के वन विभाग की गतिविधियों और प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते का पुनर्स्थापना वन विभाग की दक्षता से ही संभव हो पाया। चंबल में घडियाल और नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोडने का अनुभव अद्भुत रहा। उन्होंने कहा कि वन, वन्य जीव और क्षेत्रीय रहवासियों के बीच निर्भयता वाले संबंध वन विभाग की सेवाओं से ही संभव हो पाए। सीएम यादव ने कहा कि अगर हम डरते तो वन में जाते नहीं और वे डरते तो अटैक करते, लेकिन दोनों ने ही इसमें भागीदारी निभाई है। वन विभाग की गतिविधियों का विस्तार नभ, थल, जल सभी ओर है। इसी कारण देश में सबसे अच्छी ग्रोथ वन विभाग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएफएस मीट प्रोफेशनल संवाद के साथ ही पारिवारिक आत्मीयता और सहयोगी संबंधों को मजबूत करने का भी अवसर है। आईएफएस थीम गीत का विमोचन इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आईएफएस थीम गीत का विमोचन किया और सेवानिवृत्त आईएफएस एवं प्रदेश के पूर्व पीसीसीएफ डॉ. पीबी गंगोपाध्याय को प्रदेश के वनों की सुरक्षा और बेहतरी में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। अवार्ड गंगोपाध्याय की पत्नी गौरी गंगोपाध्याय ने प्राप्त किया कार्यक्रम में वन, पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप सिंह अहिरवार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वीएन अंबाडे और वन अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित हैं।

10वीं-12वीं की परीक्षा में प्रेक्षकों की नजर में रहेंगी आंसर शीट

परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले से लेकर कापी जमा होने तक करेंगे निगरानी

भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा को पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मंडल ने परीक्षा व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रेक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पिछले साल सिर्फ संवेदनशील व अति संवदेशील केंद्रों पर ही प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन इस बार मंडल सभी केंद्रों पर प्रेक्षकों की तैनाती होगी। माशिमं द्वारा इस बार प्रेक्षक के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं प्राचार्यों की नियुक्ति की जा रही है। इस बार प्रेक्षक केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर उनकी कड़ी नजर रहेगी। कलेक्टर की ओर से प्रेक्षक इन केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। इनकी ड्यूटी प्रश्नपत्र खुलने के आधे घंटे पहले केंद्रों पर पहुंचना होगा और परीक्षा खत्म होने के बाद प्रश्नपत्र का बंडल समवन्वयक केंद्र पहुंचाने तक की ड्यूटी रहेगी। इनकी निगरानी भी मंडल की ओर से एप के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों पर उड ?दस्तों की विशेष टीम गठित की गई है। इन केंद्रों पर विशेष निगरानी मंडल की ओर से की जाएगी। प्रदेश में करीब 700 और भोपाल जिले में 16 संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्र चिह्नित किए गए हैं। बता दें, कि मंडल की ओर से करीब 25 हजार अधिकारी व कर्मचारी तैनात किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया प्रेक्षकों की निगरानी में होगी लेक्टर द्वारा प्रेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसमें पांच साल पहले सेवानिवृत्त प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी या प्राचार्य शामिल

होंगे।इन्हें एक दिनदके लिए 700 रुपये का मानयदेय दिया जाएगा। इन्हें परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। प्रश्नपत्र एवं उत्तरपुस्तिकाओं के बंडल खुलवाने, उनका सुरक्षित वितरण, परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने और परीक्षा समाप्ति के बाद उत्तरपुस्तिकाओं को एकत्र कर जमा कराने तक की संपूर्ण प्रक्रिया प्रेक्षक की निगरानी में होगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद भी प्रेक्षक तब तक केंद्र पर मौजूद रहेंगे, जब तक सभी उत्तरपुस्तिकाएं विधिवत रूप से जमा नहीं हो जातीं। परीक्षा केंद्रों पर कोई भी घटनाक्रम होने पर इन्हें पुलिस कंट्रोल रूम, संभागीय मंडल कार्यालय में सूचना देनी होगी। सावधानी से ओएमआर शीट भरने के निर्देश इस बार विद्यार्थियों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विद्यार्थियों को उत्तरपुस्तिका के ऊपर सबसे पहले पेज पर ओएमआर शीट अत्यंत सावधानी से भरने के लिए कहा गया है। रोल नंबर, विषय कोड, नाम सहित सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरना अनिवार्य होगा।

आम बजट को गांव-गांव तक ले जाएगी भाजपा

केंद्रीय बजट की ब्रांडिंग, 15 दिन तक संवाद कार्यक्रम

भोपाल। केंद्रीय आम बजट को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश ने बड़ी रणनीति तैयार की है। इसके लिए 15 फरवरी तक मंडल से लेकर महानगरों तक बजट की खूबियों की जमकर ब्रांडिंग की जाएगी। बुद्धिजिवियों, जानकारों और जन सामान्य के बीच संवाद-चर्चा आयोजित की जाएगी। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बजट में शामिल जनकल्याणकारी प्रावधानों की सही और स्पष्ट जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचना जरूरी है। इसी उद्देश्य से संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सभी जिलों में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं। ये समितियां न केवल केंद्रीय बजट बल्कि उसके बाद आने वाले प्रदेश सरकार के बजट के प्रचार की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। जिलों में गठित होंगी विशेष समितियां निदेर्शों के अनुसार प्रत्येक जिले में एक संयोजक और पांच सदस्यों वाली समिति बनाई जाएगी। समिति में आईटी विभाग और सोशल मीडिया टीम के एक-एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा, ताकि डिजिटल माध्यमों से भी प्रभावी प्रचार किया जा सके। प्रदेश और जिला स्तर पर समितियों की संरचना एक जैसी रखी जाएगी। प्रदेश स्तर की समिति बजट से जुड़ी पूरी तथ्यात्मक जानकारी संकलित करेगी। इसमें केंद्रीय संगठन से प्राप्त बिंदुओं के साथ-साथ मध्यप्रदेश से जुड़े बजट प्रावधानों को भी विशेष रूप से शामिल किया जाएगा। यह सामग्री जिला अध्यक्षों के माध्यम से जिला समितियों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि स्थानीय स्तर पर सुनियोजित ढंग से प्रचार किया जा सके। ग्राम पंचायत तक पहुंचेगी बजट की जानकारी भाजपा का उद्देश्य है कि इस बार बजट की जानकारी केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचे। खास तौर पर युवाओं के बीच यह संदेश दिया जाएगा कि बजट आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट के बाद होंगी कार्यशालाएं केंद्रीय बजट पेश होने के तुरंत बाद प्रदेश और जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें पार्टी कार्यकताओं, जिला एवं मंडल पदाधिकारियों को बजट के प्रमुख बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही यह भी समझाया जाएगा कि जनता से संवाद करते समय किन विषयों को प्राथमिकता दी जाए। फरवरी माह के पहले पंद्रह दिनों में अधिक से अधिक लोगों तक बजट की जानकारी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि संगठित और योजनाबद्ध प्रयासों से बजट का संदेश हर वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा।

बहुत कम नंबरों में एमडी और एमएस में प्रवेश

दो राउंड के बाद भी 829 सीटें खाली

भोपाल। मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के दो राउंड पूरे हो चुके हैं। इसके बाद भी एमडी और एमएस की 829 सीटें खाली हैं। स्टेट कोटे की नीट पीजी काउंसलिंग के लिए 1400 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन डेटा के अनुसार 50 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर हैं। जिन्हें प्रवेश परीक्षा में पहिले 0 परसेंटाइल मिला था। पात्रता नियमों में छूट के चलते अब वह उम्मीदवार जो पहले अपात्र माने गए थे। वह पात्र बन गए हैं। दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 169, निजी मेडिकल कॉलेज में 660 सीट खाली रह गई हैं। काउंसलिंग के दौरान 10 निजी मेडिकल कॉलेजों की

365 सीटों के बढ़ने के कारण इस बार पीजी कोर्स में बहुत कम नंबरों पर एडमिशन हो रहे हैं। दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद भी जो 829 सीटें खाली रह गई हैं। इनको भरने के लिए कट ऑफ नीचे लाया गया है। पहले जो अभ्यर्थी अयोग्ग हो गए थे।

अब वह भी एडमिशन के लिए योग्ग हो गए हैं। विभाग के अनुसार 200 इन सर्विस डॉक्टरों ने पीजी में दाखिले के लिए एनओसी लेकर रजिस्ट्रेशन कराया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर अरुणा कुमार के अनुसार 700 सीटों पर माप अप राउंड करवाया जा रहा है। जिसके लिए लगभग 1400 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं।

"हितों" के लिए जातियों में बंटे कर्मचारी संगठन

संगठनों की आपसी बयानबाजी और विरोधाभासी मांगों के कारण प्रशासनिक निर्णय उलझे

भोपाल। मप्र में कर्मचारियों के हितों के लिए आंदोलनरत रहने वाले संगठनों का उद्देश्य समय के साथ बदल गया है। पहले कर्मचारियों के लिए आवाज उठाने वाले अधिकांश संगठन अब अपने हितों के कारण जातियों में बंट गए हैं। आलम यह है कि प्रदेश में कर्मचारी संगठनों का स्वरूप अब पूरी तरह बदल चुका है। कर्मचारी संगठनों की आपसी बयानबाजी और विरोधाभासी मांगों के कारण प्रशासनिक निर्णय उलझते जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस स्थिति के पीछे कर्मचारी संगठनों के बीच बढ़ता आपसी मनमुटाव, राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़ाव और जातिगत आधार पर नए-नए संगठन बनाना प्रमुख कारण है। इससे न केवल संगठनों की विश्वसनीयता घटी है, बल्कि सरकार के सामने कर्मचारियों की आवाज भी कमजोर पड़ी है। संगठनों जुड़े नेता अब एक-दूसरे

के खिलाफ बयानबाजी करने में जुटे हुए है। कर्मचारियों के हितों के लिए खड़े होने वाले संगठन अब से जातियों में बटकर रह गए। आज स्थिति यह है कि राजनीतिक विचारधाराओं से शुरू हुई कर्मचारी एकजुटता अब खुलकर जातिगत खेमों में बंट चुकी है। सपाक्स, अजाक्स और अपाक्स जैसे संगठन जहां सवर्ण, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों के हितों की लड़ाई का दावा कर रहे हैं, वहीं दर्जनों गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन भी इसी तर्ज पर सक्रिय हो गए हैं। इसका सीधा असर न केवल कर्मचारियों के प्रमोशन और सुविधाओं पर पड़ रहा है, बल्कि विभागों के शासकीय कामकाज पर भी दिखाई देने लगा है। इससे सरकारी कर्मचारी भी अब जातिगत खेमों में बंटते नजर आ रहे हैं।

अगले 48 घंटों में मप्र में प्रचंड ठंड, हड्डियां जमा देंगी सर्द हवाएं

मप्र के 40 इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि से बढ़ी ठंड, दिन और रात के तापमान में गिरावट

भोपाल। मप्र में बीते 48 घंटों के दौरान हुई बारिश और ओलावृष्टि ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। प्रदेश के 40 से भी अधिक जिलों में मौसम के अचानक बदले मिजाज का असर देखने को मिला। इस दौरान दिन और रात के तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों तक ठंड का असर और बढ़ सकता है। बीती रात प्रदेश में सबसे अधिक ठंड मंदसौर में दर्ज की गई। यहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में दिन का सर्वाधिक अधिकतम तापमान खंडवा में 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार सुबह ग्वालियर में वेरी डेंस फॉग दर्ज किया गया। यहां विजिबिलिटी 100 मीटर तक सिमट गई। दतिया में विजिबिलिटी 500 मीटर रही। इसी तरह रीवा, उज्जैन, खरगोन, इंदौर, नर्मदापुरम, राजगढ़ और सतना में विजिबिलिटी 500 से 1000 मीटर के बीच दर्ज की गई।

आंतरिक लड़ाइयों में उलझी मप्र कांग्रेस

आलाकमान की बैठक में भी शामिल नहीं हो रहे नेता

भोपाल। एक तरफ कांग्रेस मप्र में सत्ता की वापसी की कोशिश में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता आंतरिक लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। आलम यह है कि मप्र कांग्रेस इस वक्त अव्यवस्था, अहंकार और असफल नेतृत्व की गंभीर स्थिति से गुजर रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आलाकमान की बैठकों में भी बड़े नेता शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस को और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश के चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, डा. विक्रांत भूरिया सहित अन्य वरिष्ठ नेता अनुपस्थित रहे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस में गुटबाजी इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि नेतृत्व का कोई भी निर्णय सर्वमान्य नहीं रह गया है। विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय पार्टी अपनी ही आंतरिक लड़ाइयों में उलझी नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जहां नेतृत्व अहंकार से ग्रस्त हो, संगठन अनुशासनहीन हो और कार्यकताओं में भ्रम हो- वहां रचनात्मक राजनीति संभव नहीं होती। ऐसे हालात में विपक्ष कमजोर होता है और लोकतांत्रिक संतुलन भी प्रभावित होता है। आज की स्थिति में मप्र कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक कलह और नेतृत्व संघर्ष के केंद्र के रूप में देखी जा रही है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी यह मुद्दा उठा चुके हैं। दरअसल, पार्टी में कई नेता उपेक्षित हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के पास प्रदेश के भीतर कोई काम नहीं है। उन्हें संगठन सृजन के लिए अन्य प्रांतों में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। यही कारण है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अजय सिंह हों या फिर डा. गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया या फिर अन्य नेता, अपने-अपने क्षेत्र तक सीमित हो गए हैं। बड़े नेताओं की अनुपस्थिति पर उठे सवाल दिल्ली बैठक में बड़े नेताओं की उनुपस्थिति को लेकर मीडिया ने जब प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी से सवाल किए तो वह असहज हुए और झल्लाते हुए बोले कि किसे बुलाना है और किसे नहीं, यह हमारा आंतरिक मामला है। इस पर प्रदेश भाजपा ने तंज कसते हुए कहा है कि कमल नाथ बाहर, दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे भीतर, यही कांग्रेस की हकीकत है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की बैठक के लिए केवल प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कार्यसमिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल को बुलाया गया था। इसमें मुख्य रूप से संगठन सृजन अभियान और आगामी विधानसभा सत्र में पार्टी की भूमिका पर बात होनी थी, इसलिए केवल उससे जुड़े व्यक्तियों को बुलाया गया। दिग्विजय सिंह चूंकि प्रदेश में कांग्रेस के लिए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा

तैयार करके संगठन को दे चुके हैं, इसलिए उन्हें और कार्यसमिति का सदस्य होने के कारण कमलेश्वर पटेल को बुलाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ विदेश में हैं तो बाकी अपेक्षित नहीं थे। वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति को लेकर पूछे प्रश्न पर हरीश चौधरी ने जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसे लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि मीडिया के प्रश्न पर प्रदेश प्रभारी का तानाशाही भरा जवाब- यह पूछने का अधिकार आपको नहीं है... रहा। इसका आशय स्पष्ट है कि कांग्रेस सवालों से डरती है। उसे मीडिया की जवाबदेही स्वीकार नहीं। तो क्या इसे आंतरिक लोकतंत्र कहा जाए? कांग्रेस में लोकतंत्र केवल भाषणों तक सीमित है। भाजपा ने ली चुटकी वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने लिखा है कि मप्र कांग्रेस अव्यवस्था, अहंकार और असफल नेतृत्व की मिसाल! जब प्रदेश प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष को ही दिल्ली जाकर अपनी पार्टी की अनुशासनहीनता गिनानी पड़े- तो समझिए नेतृत्व फेल है। जब अपने ही नेता प्रदेश अध्यक्ष की क्षमता पर सवाल उठाएं- तो समझिए संगठन खोखला है। और जहां न विश्वास है, न दिशा, न जवाबदेही- वहां राजनीति नहीं, सिर्फ अराजकता बचती है। मप्र कांग्रेस आज विपक्ष नहीं, आंतरिक कलह का संग्रहालय बन चुकी है। पार्टी के भीतर हालात तब और चिंताजनक हो गए, जब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष की कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इससे साफ है कि संगठन में न तो आपसी भरोसा बचा है और न ही स्पष्ट दिशा या जवाबदेही।

भाजपा ने शुरू की जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की तैयारी...

मोर्चा और प्रकोष्ठों में नियुक्ति के लिए विधायकों से मांगे नाम

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी अब अपने मोर्चा और प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्षों की सूची जारी करने की तैयारी कर रही है। हालांकि प्रदेश में अध्यक्ष तो बना दिए गए हैं, लेकिन उनकी कार्यकारिणी लंबित पड़ी है, वहीं जिलाध्यक्षों ने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से राय-मशविरा लेना शुरू कर दिया है। भाजपा अब संगठन विस्तार को नया रूप देने जा रही है। हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बने काफी समय हो गया है और उन्होंने अपनी कार्यकारिणी के साथ-साथ मोर्चा और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी है। कुछ मोर्चा और प्रकोष्ठ बाकी है, जिन पर नियुक्ति की जाना है। पार्टी चाह रही है कि जल्द से जल्द इनकी भी घोषणा कर दी जाए। इसलिए सभी प्रदेश अध्यक्षों को अपनी-अपनी कार्यकारिणी बनाने के लिए भी कहा गया है। मोर्चा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी की जाना है। फरवरी माह में कुछ जिलों में मोर्चा और प्रकोष्ठ के नए अध्यक्ष मिल जाएंगे। पार्टी चाह रही है कि अगले साल होने वाले निकाय चुनावों से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक इनकी नियुक्ति रहेगी, इसलिए इन पर दमदार नेताओं के नाम मंगवाए जाएं। जिलाध्यक्षों ने इस पर चर्चा करना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल विधायकों से कहा गया है कि उनके क्षेत्र में जो भी दावेदार हो, उसकी जानकारी निकालकर नाम दिया जाए। युवा मोर्चा में उम्र का बंधन रहेगा और मात्र 40 साल तक के युवाओं को ही इसमें मौका दिया जाएगा, वहीं युवा मोर्चा के साथ-साथ महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ-साथ अन्य प्रकोष्ठ के लिए भी नाम निकाले जा रहे हैं। पिछली बार के मोर्चा पदाधिकारियों के कामों का आकलन भी किया जा रहा है, ताकि जो सक्रिय हो, उसे प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया जा सके। पार्टी युवा और महिला मोर्चा पर सशक्त और सर्वमान्य नाम तलाशने का कह चुकी है, क्योंकि ये दोनों ही मोर्चा चुनाव और अन्य कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश के सूत्रों का कहना हैकि प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में देर नहीं की जाएगी, क्योंकि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को सालभर हो गया है और उन्हें पुराने मोर्चा-

कंपनियों को उपकृत करने ताक में रखे भंडार क्रय नियम

संदेह के घेरे में उच्च शिक्षा विभाग के एपीडी व ओएसडी की भूमिका

भोपाल। कंपनियों को उपकृत करने उच्च शिक्षा विभाग में भंडार क्रय नियमों को ताक में रखने का मामला सामने आया है। जिसमें अतिरिक्त परियोजना संचालक एवं ओएसडी सुनील सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं। आरोप है कि अन्य एजेंसियों को प्रतियोगिता से बाहर कर चहेती कंपनियों की योग्यता अनुसार मनमानी शर्तें जोड़ी गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव व उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को भेजी गई शिकायत में सप्लायर एसके शर्मा द्वारा इस निविदा को निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही अतिरिक्त परियोजना संचालक सुनील ढूषसह पर आरोप लगाया है कि इनके द्वारा चहेते सप्लायर कंप्यूटर लैब पेगासस को 80 करोड़ का आईसीटी टेंडर एवं हेवेन टेक्रों सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एंड सीपी प्लस को 30 करोड़ का टेंडर के लिये लिये 2023-23 के भंडार क्रय नियम दरकिनार किये गये हैं। विभागीय मंत्री के पीए के बरदहस्त के कारण शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। जबकि अन्य कंपनियों को बाहर करने बाद अकेले बची इन कंपनियों का ही टेंडर शुक्रवार मंजूर करने की तैयारी की जा चुकी है। लगातार शिकायतें हुई नजर अंदाज इस टेंडर मामले में पहले रोहित गुंजाल द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। जिसमें विश्व बैंक की रूसा परियोजना के अतिरिक्त परियोजना संचालक सुनील सिंह व ओएसडी आजाद मंसूरी को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया था कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 250 करोड़ रुपए के टेंडर क्रमांक 2025 में मप्र भंडार क्रय नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जिससे व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए चहेतों को अनाधिकृत उपकृत किया जा सके। बावजूद इसके विभागीय अधिकारियों ने इसे संज्ञान नहीं लिया। बता दें कि विश्व बैंक की रूसा परियोजना के तहत 179 कॉलेजों में फर्नीचर, 108 में कंप्यूटर लैब और 15 मूट कोर्ट बनाये जाने हैं।

|| संपादकीय ||

शिक्षा में समता या नई असमानता: यूजीसी नियमों पर न्यायिक विराम

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नाम पर लागू किए गए नए नियमों ने देश के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में एक बार फिर गहरी हलचल पैदा कर दी है। जिस नीति को 'समता', 'समान अवसर' और 'समावेशी शिक्षा' की भावना से जोड़कर प्रस्तुत किया गया, वह व्यवहार में आते ही एक वर्ग विशेष के तीव्र विरोध, व्यापक असंतोष और सामाजिक तनाव का कारण बन गई। स्थिति इतनी विकट हुई कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर इन नियमों पर अंतरिम रोक लगानी पड़ी। यह रोक न केवल सरकार की नीति-निर्माण प्रक्रिया पर एक प्रश्नचिह्न है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण और असंतुलित प्रयोग देश को किस दिशा में ले जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप किसी नीति के समर्थन या विरोध का सीधा निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक चेतावनी है कि समानता के नाम पर लागू किए गए नियम यदि अस्पष्ट हों, दुरुपयोग की संभावना रखते हों और सामाजिक सौहार्द को बाधित करते हों, तो वे न्यायिक समीक्षा से परे नहीं रह सकते। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह माना कि यूजीसी के नए नियमों में स्पष्टता का अभाव है और यही अस्पष्टता उन्हें विवादास्पद बनाती है। यह रोक सरकार को आत्ममंथन का अवसर देती हैकृएक ऐसा अवसर जिसे राजनीतिक टकराव के बजाय सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि जो सरकार बार-बार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की बात करती रही है, वह शिक्षा संस्थानों जैसे विचार-निर्माण के केंद्रों में ऐसे नियम क्यों लाई, जिनसे जातिगत पहचान और वर्गीय विभाजन की रेखाएँ और गहरी होने की आशंका पैदा हो गई। भारत का सामाजिक इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जाति के नाम पर की गई किसी भी नीति ने, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही कल्याणकारी क्यों न रहा हो, समाज को भीतर ही भीतर विभाजित किया है। आरक्षण जैसी संवैधानिक व्यवस्था सामाजिक न्याय के लिए लाई गई थी, लेकिन इसके लंबे प्रयोग ने देश को ऐसे घाव भी दिए हैं, जिनका उपचार आज तक पूर्ण रूप से नहीं हो सका। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत आधार को और उभारने वाली किसी भी पहल को लेकर स्वाभाविक रूप से आशंका उत्पन्न होती है।

शिक्षा संस्थान केवल डिग्री बांटने की फैक्ट्रियां नहीं होते; वे समाज की दिशा तय करने वाली प्रयोगशालाएं होते हैं। यहां तैयार होने वाला छात्र केवल नौकरीपेशा व्यक्ति नहीं, बल्कि भविष्य का नागरिक होता है। यदि यही परिसर अविश्वास, वर्ग-संघर्ष और परस्पर शंका के केंद्र बन जाएं, तो इसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करता है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर उठा विरोध इसी आशंका का प्रकटीकरण है। यह भी विचारणीय है कि समानता और समता के बीच का अंतर नीति-निर्माण में किस हद तक समझा गया। समानता का अर्थ है सबके साथ एक जैसा व्यवहार, जबकि समता का अर्थ है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित अवसर देना। यदि समता के नाम पर ऐसे प्रावधान किए जाएं जो एक नए प्रकार की असमानता को जन्म दें, तो वह नीति अपने उद्देश्य से भटक जाती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसी बिंदु की ओर संकेत करती है कि नियमों का उद्देश्य भले ही सकारात्मक रहा हो, लेकिन उनकी संरचना और भाषा ने विवाद और भ्रम को जन्म दिया।

यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग तेजी से हावी होता गया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसे अपने-अपने हितों के चश्मे से देखना शुरू कर दिया, वोट बैंक की राजनीति से इसे देखा जाने लगा जबकि यह विषय मूलतः शिक्षा सुधार और सामाजिक संतुलन से जुड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई अवसरों पर यह कहते रहे हैं कि शिक्षा को राजनीति से मुक्त रखा जाना चाहिए और नीतियां दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यूजीसी द्वारा बनाए गए इन नियमों में उस दूरदर्शिता और संतुलन का अभाव क्यों दिखा? लगता है कि यूजीसी ने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे इसे लागू कर दिया,यदि यूजीसी ने व्यापक संवाद, सभी पक्षों से परामर्श और संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं का पूर्व आकलन किया होता, तो शायद यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। नीति बनाते समय केवल कानूनी वैधता पर्याप्त नहीं होती; सामाजिक स्वीकार्यता और नैतिक संतुलन भी उतने ही आवश्यक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश के माध्यम से यही संकेत दिया है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी बदलाव से पहले उसके दूरगामी प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

नए नियमों की सबसे बड़ी कमजोरी एवं त्रासदी यही रही कि वे आरक्षित और सामान्य वर्गों को एक-दूसरे के सामने खड़ा करके विद्रोह एवं विरोध में खड़ा कर दिया। यह विभाजनकारी प्रवृत्ति न केवल शिक्षा के वातावरण को दूषित करती है, बल्कि उस राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को भी कमजोर करती है, जिसकी बात हम संविधान में करते हैं। किसी भी नीति का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह समाज को जोड़ती है या तोड़ती है। यदि वह अविश्वास और टकराव को बढ़ावा देती है, तो उस पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सुधार का अवसर है-सरकार, यूजीसी और समूचे शैक्षिक तंत्र के लिए। यह समय है कि भावनाओं और राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर एक ऐसी नीति बनाई जाए, जो वास्तव में समान अवसर सुनिश्चित करे, लेकिन बिना किसी नए विभाजन को जन्म दिए। शिक्षा में सुधार का अर्थ समाज को आगे ले जाना है, न कि पुराने घावों को फिर से कुरेदना।

देश को ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो प्रतिभा को जाति से ऊपर रखे, अवसर को पहचान से मुक्त करे और परिसरों को संघर्ष का नहीं, संवाद का केंद्र बनाए। सुप्रीम कोर्ट की यह रोक उसी दिशा में एक संकेत है। अब यह सरकार और यूजीसी की जिम्मेदारी है कि वे इस संकेत को समझें, आत्मावलोकन करें और ऐसे नियम गढ़ें जो वास्तव में भारत की समावेशी, संतुलित और भविष्यद्रष्टा संरचना के अनुरूप हों। यदि इस अवसर को भी राजनीतिक स्वार्थ की भेंट चढ़ा दिया गया, तो यह केवल एक नीति की विफलता नहीं होगी, बल्कि उस विश्वास की भी हार होगी, जो जनता ने शिक्षा सुधारों से जोड़ रखा है।

- ललित गर्ग

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

हिमालय क्षेत्र की बर्बादी से नेताओं को नहीं कोई सरोकार

देश के राजनीतिक दल देश के लोगों के लिए कितने गैरजिम्मेदार हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमालय क्षेत्र में शोध पर आधारित दो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जानकारी के बारे में किसी ने चिंता तक जाहिर नहीं की। इन रिपोर्टों में सर्दी के मौसम में हिमालय क्षेत्र जंगलों में लगने वाली आग के कारण और भूस्खलन के नए केंद्रों की जानकारी दी गई है। दरअसल ऐसी जानकारियों को गंभीरता से लेने पर राजनीतिक दलों के वोट बैंक में इजाफा नहीं होता। यही वजह है अत्यंत संवेदनशील और आम जन—जीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरण जेसे मुद्दे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में जगह नहीं पाते हैं।

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि इस बार सर्दियों का मौसम शुरू होने के बाद 1 नवंबर से अब तक उत्तराखंड में देश में सबसे अधिक 1,756 फायर अलर्ट दर्ज किए गए हैं। यह संख्या महाराष्ट्र (1,028), कर्नाटक (924), मध्य प्रदेश (868) और छत्तीसगढ़ (862) जैसे उन राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है, जो पारंपरिक रूप से जंगल में आग के मामले में अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। आमतौर पर दिसंबर जंगल में आग के लिहाज से सबसे शांत महीना माना जाता है, लेकिन पिछले तीन सालों में उत्तराखंड के लिए यह धारणा गलत साबित हुई है। दिसंबर में उत्तराखंड में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। जंगल की जमीन में नमी का लेवल बहुत कम है। उत्तराखंड की तरह, हिमाचल में भी पिछले साल अक्टूबर के पहले सप्ताह से कोई बारिश नहीं हुई थी।

इसी तरह, कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा जैसे प्रमुख सेब उत्पादक इलाकों में भी बर्फबारी लगभग न के बराबर हुई है। इस वजह से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। इस पूरे परिदृश्य को अब पर्यावरण प्रदूषण से जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बार-बार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। देहरादून में तो कई बार यह इंडेक्स 300 के पार जा चुका है, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की ओर से कराए गए एक अध्ययन ने चिंता और बढ़ा दी है। रिपोर्ट में सामने आया कि पर्यावरण प्रदूषण में फॉरेस्ट फायर की भूमिका 15 से 20 प्रतिशत तक है, जो कि बेहद गंभीर आंकड़ा है।

> इसी तरह, कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा जैसे प्रमुख सेब उत्पादक इलाकों में भी बर्फबारी लगभग न के बराबर हुई है। इस वजह से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। इस पूरे परिदृश्य को अब पर्यावरण प्रदूषण से जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बार-बार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच रहा है।

उत्तराखंड का हिमालयी भूगोल, जलवायु परिवर्तन और तेज विकास की दौड़ मिलकर राज्य के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में राज्य में तेज गति से सड़क निर्माण और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए हैं। इसका परिणाम यह निकला कि चारधाम यात्रा रूट के आसपास लगभग 100 नए भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए। पहले से मौजूद संवेदनशील जोन भी और अधिक खतरनाक हो गए हैं। चारधाम यात्रा और पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन तेजी से निर्माण कार्यों ने पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना को कमजोर किया है। सड़क और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग की गई, भारी मशीनरी का उपयोग हुआ, जंगलों का व्यापक कटान किया गया। इन सभी वजहों से पुराने भूस्खलन क्षेत्र सक्रिय हुए और नए भूस्खलन क्षेत्र भी बन गए। उत्तराखंड के नेशनल हाईवे नेटवर्क पर करीब 400 भूस्खलन स्थल चिन्हित किए गए हैं।

उत्तराखंड में मानसून सीजन में हर साल प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान होता है। साल 2025 के मानसून सीजन में अब तक उत्तराखंड में रिकॉर्ड बारिश हुई है। उत्तराखंड में 2016 से 25 तक प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई है। पिछले 11 वर्षों में 27,197 प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें अतिवृष्टि और भूस्खलन की घटनाएं प्रमुख हैं। साल 2025 में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुईं, जिसमें 720 लोगों की मौत और 1207 लोग घायल हुए थे। इन 11 सालों के आंकड़े में केदारनाथ की साल 2013 में 16 और 17 जून को आई प्राकृतिक आपदा के आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं। उस दौरान अकेले केदारनाथ में ही 4400 से ज्यादा लोग या तो लापता हो गए थे या फिर मारे गए थे।

हिंदुकुश हिमालय का इलाका भारत, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। यहां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी 11 बड़ी नदियां बहती हैं। वसंत के महीने में बर्फ पिघलने से ही इन नदियों को पानी मिलता है। लगभग 17 प्रतिशत आबादी पीने के पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है। इसी पानी का उपयोग सिंचाई और हाइड्रोपावर के लिए भी किया जाता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के तापमान में वैश्विक औसत से 0.74C अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साल 2003 से 2020 तक हिमालय के अधिकांश हिस्सों में बर्फ से घिरे इलाकों में गिरावट देखी गई। पहले यहां औसतन 102 दिनों तक बर्फ रहती थी। अब हर दस साल में पांच दिन कम हो रहे हैं।

भारत के मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभों के कमजोर होने से पिछले साल दिसंबर में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में न के बराबर बर्फ गिरी। गढ़वाल में इस साल जनवरी में बर्फबारी का अभाव देखा गया। ऐसा पिछले 40 सालों में पहली बार हुआ है। कम हिमपात के चलते जटामांसी और कुटकी जैसी महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ीबूटियां विलुप्त हो रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों में स्नो ड्रॉट या 'बर्फ का सूखा' जैसी स्थिति बन रही है। विशेष रूप से 3,000 से 6,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह प्रभाव सबसे अधिक देखा गया है।

हिमाचल प्रदेश में बेलगाम विकास से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुका है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल एक दिन नक्शे से गायब हो जाएगा। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाबतलब किया। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल में भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएं मानव निर्मित हैं। बिना वैज्ञानिक अध्ययन के फोर लेन रोड बन रहे हैं और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। उनके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ों को बारूद से उड़ाया जा रहा है। सिर्फ राजस्व कमाना सब कुछ नहीं। पर्यावरण के विनाश की कीमत पर ऐसी कमाई हिमाचल के अस्तित्व को ही खत्म कर देगी। आश्चर्य की बात यह है कि राजनीतिक दलों को जो काम करना चाहिए उसे सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। अभी भी वक्त है हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण की यदि सुध नहीं ली गई कि तो भविष्य में ज्यादा गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे।

- योगेन्द्र योगी

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

पर्यटन के बूट

पर्यटन के रास्ते आ रहा फूहड़पन और हिमाचल की तस्वीर में बहती गंदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अक्सर सोशल मीडिया के खंडहर स्थापित हो जाते हैं। हिमाचल में ऐसा बहुत कुछ है जो आह्लादित और रोमांचित करता है। यहां हर मौसम दिल तक के रंग बदलता है। मसलन बर्फ के सान्निध्य में पर्यटन का उफान आजकल जिस कद्र छाया है, उसके साथ खुली छूट नहीं दी जा सकती। बर्फ का कचूमर निकालना पर्यटन नहीं और न ही वाहनों से खेलना पहाड़ की सोहबत है। वे दृश्य भयानक हैं जब रिज पर गिरी बर्फ से नहाते पर्यटक अगर अपनी आस्तीन खोल दें या निर्वस्त्र होकर कोई महिला मनाली की फिाा बिगाड़ दे। इस शोरगुल में बर्फ भी बहरी हो गई, प्रकृति गाती रही हम भी सुन न सके। प्रकृति की छूअन का हल्का सा आमंत्रण आंखों में बहारों सा शगुन है, लेकिन पर्यटन के अति दोहन ने हमसे हमारी मौलिकता छीन ली है। हिमाचल को मौसमी पर्यटन की महफिल जरूर मिलती है, लेकिन यह चार दिन की चांदनी बनकर प्रदेश के ओज को बौना कर देती है। ऐसे पर्यटन के आगे जो देखा जा सकता है, उसे कैसे बचाएं-दिखाएं। यह नागरिक जवाबदेही भी है कि पर्यटन को प्रकृति की रचना में संजोएं। तारीफ करनी होगी लाहौल-स्पीति के सिस्सू-कोकसर इलाके के लोगों की, जिन्होंने अपने हलडा उत्सव की मर्यादा को कायम रखते हुए 40 दिनों तक पर्यटन गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह इसलिए भी कि अटल टनल ने पर्यटन को दरिया बना दिया है और अगर सिस्सू के नागरिक, आमंत्रण और परंपरा के बीच पहाड़ के मर्म की रक्षा न करते तो सैलानियों के बूट किसी भी स्तर तक पहुंच कर कुछ भी रौंद देते। यही सब इस बर्फबारी के मंजर में तबाह भी हुआ है। आखिर बर्फ केवल पर्यटन के लिए ही तो नहीं आती। वह पहाड़ को पहाड़ की दरियादिली में दिखाने के लिए आती है। वह कृषि, फलोत्पादन व नदियों के प्रवाह में आत्मविश्वास लेकर आती है। इसलिए बर्फ के हर गिरे हुए फाहे पर पर्यटन का हक नहीं हो सकता। इसी तरह प्राकृतिक हलचल या प्राकृतिक छटा के हर मजमून से सोशल मीडिया को आबाद करना भी गुनाह है। कोई महिला बाहर से आकर मनाली के सार्वजनिक शिष्टाचार भूल कर नग्नावस्था में अश्लील डांस करे, तो इससे भयानक पर्यटन आकर्षित होगा।

अभी भी अंतरराष्ट्रीय हलकों में मलाणा क्रीम का जिक्र मात्र हिमाचल को नशे की मंडी बना देता है। धीरे-धीरे हिमाचल के ही कुछ इलाके गोपनीय पार्टियों के इश्तिहार में बदनाम हो चुके हैं। आखिर 70 लाख की आबादी वाले पहाड़ी, परंपरावादी, कबायली व खास मूल्यों से प्रेरित हिमाचल को कितना और किस तरह के पर्यटन की जरूरत है। हमें पर्यटक परिवार चाहिए, कारपोरेट जगत की युवा पीढ़ी चाहिए, हुल्लड़बाज युवा चाहिए या रील बनाने की उद्दंडता से सराबोर सैलानी चाहिएं। हमारी पर्यटन की मुहिम न पर्यटन सीजन और न ही बर्फबारी या शीतकालीन सफर तक मुकम्मल होती है। जो डलहौजी की बर्फ को रौंद रहे हैं, उन्हें कौन बताएगा चंबा के हजार साल की धरोहर। शिमला में बर्फबारी से इतर ब्रिटिश पीरियड की यादों के झरोखे कौन खोलेगा।

टेक्नोलॉजी

भारी पड़ सकती हैं ये चीजें, फोन पर भूलकर भी न करें यूज, हो जाएगा बड़ा नुकसान

अब फोन सिर्फ दुनिया से कनेक्ट होने का जरिया नहीं बच गए हैं. अब इनमें हमारी बैंकिंग इंफोर्मेशन, पेमेंट डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट तक सब कुछ स्टोर होता है. इसलिए कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. कई लोग ट्रेंड को फॉलो करते हुए फोन के साथ कुछ ऐसी गड़बड़ कर लेते हैं, जिसका बड़ा नुकसान हो सकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोन को किन चीजों से बचाकर रखना चाहिए.

फोन के बैक पैनल पर न लगाएं स्टिकर्स - स्टिकर देखने में अच्छे होते हैं और फोन को नया लुक भी देते हैं, लेकिन ये बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं. अगर आप किसी मोटे मैटेरियल से बने स्टिकर से फोन का पूरा बैक पैनल कवर कर लेते हैं तो इससे ओवरहीटिंग की समस्या आ सकती है. इसके अलावा जब आप स्टिकर को हटाते हैं तो फोन पर इसका निशान रह जाता है, जिससे लुक खराब हो सकता है. अगर आपको

स्टिकर पसंद हैं तो आप फोन के बैक पैनल की जगह कवर पर इन्हें लगा सकते हैं.

प्लास्टिक के स्क्रीन प्रोटेक्टर - फोन की स्क्रीन को स्क्रैचेज से बचाने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर की जरूरत होती है, लेकिन सभी प्रोटेक्टर एक तरह से काम नहीं करते. प्लास्टिक के स्क्रीन प्रोटेक्टर सस्ते जरूरी होते हैं, लेकिन जोर से गिरने पर स्क्रीन को डैमेज होने से नहीं बचा सकते. इसके अलावा खराब क्वालिटी वाले प्रोटेक्टर से स्क्रीन की टच सेंसेटिविटी भी कमजोर होती है. इसलिए प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर की जगह टेम्पर्ड ग्लास यूज करें. यह स्क्रीन को बेहतर प्रोटेक्शन दे पाएगा.

रैम क्लीनर और बैटरी सेवर ऐप्स- अगर कोई ऐप रैम क्लीन करने, फोन की स्पीड बढ़ाने या बैटरी सेव करने का क्लेम कर रही है तो ऐसी ऐप्स से बचकर रहे. ये ऐप्स आपके फोन से डेटा कलेक्ट करने के अलावा कोई काम नहीं कर सकती. कई बार साइबर अटैकर्स ऐसी ऐप्स डाउनलोड करवा लेते हैं, जिससे उनके लिए डेटा चोरी करना आसान हो जाता है. इसलिए ऐसी ऐप्स से अपने फोन को बचाकर रखें.

जनरल नॉलेज

किस देश में अब भी सबसे सस्ता है सोना, वहां से कितना गोल्ड भारत ला सकते हैं?

सस्ते सोने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है. अमेरिका में 30 जनवरी को 24 कैरेट सोना करीब 15,905 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 15,078 रुपये रुपये प्रति ग्राम के आसपास रहा है.

भारत में सोने-चांदी की कीमत आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है. अब हालात ऐसे हैं कि अब सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी खरीदना भी लोगों के बजट पर भारी पड़ रहा है. 30 जनवरी 2026 को देश में चांदी का भाव करीब 3 लाख 95 हजार रुपये प्रति किलो पहुंच गया, जबकि 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1 लाख 70 हजार रुपये और 22 कैरेट सोना 1 लाख 56 हजार रुपये पर पहुंच गया. हालांकि अब सोने और चांदी की कीमतों आज थोड़ी राहत मिली है.

फिर भी सोने और चांदी के बदलते दामों के चलते इस समय शादी ब्याह और निवेश के लिए सोना खरीदना लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अब भी किस देश में सोना सबसे सस्ता है और वहां से कितना गोल्ड भारत ला सकते हैं.

किस देश में अब भी सोना है सस्ता? - भारत में सोने की कीमत टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और ज्यादा मांग की वजह से ऊंची रहती है. 2025 में दुनियाभर में गोल्ड के दाम बढ़े है जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है. हालांकि, कुछ देश ऐसे हैं जहां टैक्स पॉलिसी करेंसी वैल्यू और बाजार की कंडीशन के कारण सोना भारत के मुकाबले काफी सस्ता मिल रहा है. इन सस्ते सोने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है. अमेरिका में 30 जनवरी का 24 कैरेट सोना करीब 15,905 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 15,078 रुपये और 18 कैरेट सोना 12,317 रुपये प्रति ग्राम के आसपास रहा है. भारत के मुकाबले यह कीमतें काफी कम हैं. अगर कोई भारतीय पुरुष या महिला अमेरिका में 6 महीने या उससे ज्यादा समय से रह रहे हैं तो पुरुष 20 ग्राम यानी करीब 50 हजार रुपये और महिलाएं 40 ग्राम यानी करीब 1 लाख रुपये तक का सोना बिना कस्टम ड्यूटी के भारत ला सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया भी सस्ता गोल्ड देने वाला देश - दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, जो दुनिया के बड़े सोना उत्पादक देशों में शामिल है. यहां 24 कैरेट सोना लगभग 15,000 रुपये प्रति ग्राम में मिल जाता है. जबकि 22 और 18 कैरेट गोल्ड इससे भी सस्ता है. ऑस्ट्रेलिया से भी वही नियम लागू होते हैं, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने या उससे ज्यादा समय से वहां रह रहा है तो तय सीमा तक सोना बिना कस्टम ड्यूटी के भारत ला सकता है.

सिंगापुर बना एशिया का सस्ता गोल्ड हब - तीसरे नंबर पर सिंगापुर है जिसे एशिया की सस्ती गोल्ड मार्केट माना जाता है. यहां टैक्स की दरें बहुत कम है और यह देश गोल्ड ट्रेडिंग का बड़ा हब है. सिंगापुर में 24 कैरेट सोना करीब 14,300 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 12,845 रुपये प्रति ग्राम मिलता है. अगर कोई भारतीय एक साल या उससे ज्यादा समय से सिंगापुर में रहा है, तो वह भी तय सीमा तक सोना बिना कस्टम ड्यूटी भारत ला सकता है.

इन देशों से भी मिल सकता है सस्ता सोना - अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के अलावा भारतीय इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, दुबई, भूटान, मलावी और कोलंबिया से भी सस्ता सोना खरीद सकते हैं. दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है.

बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी के अमीर ने भारत को दी मनचाही राहत, रिश्तों पर कयिा बड़ा ऐलान

एजेंसी ढाका

बांग्लादेश में चुनाव से पहले भारत के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। बांग्लादेश की पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमात- ए- इस्लामी के अमीर शफीकूर रहमान ने कहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो भारत को कोई तकलीफ नहीं देंगे। रहमान से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि अगर भारत शेख हसीना को सौंपने से इंकार कर देता है तो जमात-ए-इस्लामी क्या कदम उठाएगी। इस सवाल के जवाब में जमात के अमीर ने कहा, 'हम भारत के साथ सार्थक बातचीत करेंगे। हमारी पार्टी का रुख साफ है कि हम अपने पड़ोसियों को कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। इसके बदले में हम उनसे भी आपसी सम्मान और भरोसे की उम्मीद करते हैं।'जमात-ए-इस्लामी के चीफ ने अलजजीरा टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। रहमान ने साल 1971 में बंगाली लोगों के खिलाफ हुए भयानक अत्याचार में अपनी पार्टी के शामिल होने के आरोप को भी खारिज किया। उन्होंने कहा, 'जमात ने उस समय जो फैसला लिया था, वह एक राजनीतिक फैसला था। किसी हथियार बंद बल का नहीं। उस समय हमारे नेताओं का मानना था कि भारत की मदद से पाकिस्तान से अलग होने पर बांग्लादेश पर एक नए रूप में भारतीय प्रभुत्व कायम हो जाएगा।'

रहमान ने कहा कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने खुद जो युद्ध अपराधियों की लिस्ट तैयार की थी, उसमें सभी पाकिस्तानी सैनिक थे। इसमें कोई भी बांग्लादेश की जमीन का नहीं था। इस बीच जमात-ए-इस्लामी न केवल भारत के प्रति नरम रुख अपना रही है, बल्कि शेख हसीना को अब तक सपोर्ट करने वाले हिंदुओं को भी साध रही है। खुद रहमान ने हिंदुओं से अपील की है कि वे आगामी चुनाव में उनकी पार्टी को सपोर्ट करें। खुलना 1 संसदीय सीट पर एक रैली को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा कि वह चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों के लिए सुरक्षित बांग्लादेश बने।

खुलना 1 संसदीय सीट पर हिंदुओं का बहुमत है। इस सीट के लिए जमात ने अपने स्थानीय हिंदू समिति के अध्यक्ष नांदी को अपना उम्मीदवार चुना है। यहां पर हिंदू उम्मीदवारों के चुने जाने का इतिहास रहा है। नांदी जमात के महासचिव मिआ गोलम के करीबी हैं और उनके साथ अक्सर देखे जाते हैं। जमात चीफ ने उद्योगों से भी कहा है कि वे सभी लोगों को धार्मिक भेदभाव के बिना समान अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को न्याय के आधार पर उसका हक देंगे। हम इसमें धर्म नहीं देखेंगे और सही उम्मीदवार पर भरोसा करेंगे। भारतीय राजनयिक से मुलाकात का हाल ही में खुलासा करने वाले रहमान ने कहा, 'हमने यह कहा है कि यह देश केवल मुस्लिमों का नहीं है। हां, मुस्लिम यहां पर बहुमत में हैं लेकिन यह देश एकता का फूलों का बगीचा है। यहां पर तीन और धर्मों के लोग रहते हैं। हम उनके सम्मान और उनके जीवन रूपी संपत्ति के चौकीदार हैं। उनको कोई भी बुरी नजरों से देख नहीं पाएगा। कोई भी उनको निशाना नहीं बना पाएगा।' उन्होंने बीएनपी के तारिक रहमान पर भी निशाना साधा और कहा कि परिवार आधारित राजनीति का इस देश से अंत होगा। बीएनपी और जमात दोनों ने ही हिंदुओं की सुरक्षा का वादा किया है। भारत भी मोहम्मद यूनुस सरकार से मांग कर रहा है कि वह हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। यूनुस सरकार इसमें फेल साबित हो रही है।

तुर्की के बदले सुर, पाकिस्तान को दो टूक- `बाहरी ताकतों के दम पर न रहें', सऊदी अरब को भी झटका

एजेंसी अंकारा

तुर्की ने इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। विदेश मंत्री हाकान फिदान ने यह साफ कर दिया है कि तुर्की किसी नए भू-राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि तुर्की किसी नए भू-राजनीतिक गुट को बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता है, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित भरोसेमंद क्षेत्रीय एकजुटता मंच बनाने की पहल करता है। इससे पहले ऐसी अटकलें थी कि तुर्की पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा समझौते में शामिल होगा। ऐसे में इस बयान को सऊदी अरब के लिए भी एक झटका माना जा रहा है। फिदान ने कहा, "अपनी सुरक्षा आउटसोर्स न करें।" उन्होंने तर्क दिया कि क्षेत्र में मुख्य समस्या सिर्फ बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच भरोसे की गहरी कमी है। उनके अनुसार, जब तक क्षेत्रीय देश अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक स्थिरता नहीं आ सकेगी। तुर्की के लिए, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एकजुटता, संस्थागतकरण और आखिरकार ऐसे समझौते और मंच बनाने की जरूरत है जो बाहरी शक्तियों पर निर्भरता के बजाय साझा हितों को दर्शाते हों। फिदान ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी कोई भी व्यवस्था समावेशी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "कोई तुर्की प्रभुत्व नहीं, कोई अरब प्रभुत्व नहीं, कोई फारसी प्रभुत्व नहीं, कोई अन्य प्रभुत्व नहीं।" उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तुर्की का लक्ष्य जिम्मेदार क्षेत्रीय कार्रवाई है, न कि कोई पदानुक्रम बनाने का है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि एक मंच दो या तीन देशों से शुरू हो सकता है, लेकिन समय के साथ इसे सर्व-समावेशी बनने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने बार-बार नियमों पर आधारित सहयोग और क्षेत्रीय स्वामित्व पर जोर दिया। तुर्की इन दिनों मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। सऊदी अरब के साथ तुर्की के संबंध मजबूत हुए हैं। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ तुर्की की दूरियां बढ़ी हैं। मध्य पूर्व के सबसे ज्वलंत मुद्दे फिलिस्तीन पर भी तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान एकमत हैं। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात ने अब्राहम समझौते में शामिल होकर इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया है। वहीं, तुर्की-इजरायल संबंधों में गाजा युद्ध को लेकर गंभीर तनाव है।

ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्सः टॉप 10 देशों की लिस्ट में US का ताज छीनने के करीब चीन, भारत-पाकिस्तान की रैंकिंग

एजेंसी वॉशिंगटन

अमेरिका ने बिना सैन्य ताकत के बनाए जाने वाले प्रभाव यानी सॉफ्ट पावर में भी अपनी बादशाहत कायम रखी है। साल 2026 के ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर बरकरार है। हालांकि अमेरिका का स्कोर इस साल घटा है जबकि चीन का बढ़ा है। ऐसे में शीर्ष दो पर मौजूद इन दोनों ताकतवर देशों में फासला काफी कम हो गया है। वहीं भारत इस लिस्ट में कोई उल्लेखनीय स्थान पाने में नाकाम रहा है। इस इंडेक्स में यूएन के 193 सदस्य देशों को 55 पैमानों पर रैंक करते हुए उनको स्कोर दिया गया है। ब्रांड फाइनेंस सॉफ्ट पावर की लिस्ट में अमेरिका ने 100 में से 74.9 स्कोर के साथ टॉप पर जगह बनाई है। हालांकि अमेरिका इस बात से निराश होगा कि पिछले साल की तुलना में 4.6 अंकों की गिरावट उसके स्कोर में हुई है। अमेरिका के बाद चीन दूसरे स्थान पर है। चीन इस साल इंडेक्स में एकमात्र ऐसा देश है, जिसके सॉफ्ट पावर स्कोर में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। 35 नेशनल ब्रांड विशेषताओं में से 19 में चीन की रैंकिंग बेहतर हुई है। चीन का स्कोर 0.7 अंक बढ़कर 73.5 हो गया है। इससे अमेरिका से उसका अंतर 1.5 अंक से भी कम रह गया है। जापान इस लिस्ट में 70.6 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं यूके 69.2 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। यूके के लिए यह इस इंडेक्स की शुरुआत के बाद से उसकी सबसे निचली रैंक है। दूसरे कई पश्चिमी देशों के स्कोर में भी गिरावट का ट्रेंड इस साल देखा गया है। इस वर्ष जर्मनी पांचवें (67.7 स्कोर) और फ्रांस छठवें (65.8 स्कोर) स्थान पर है। स्विट्जरलैंड एक स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर आ गया है। स्विट्जरलैंड को उच्च स्तर के भरोसे, प्रभावी शासन और आर्थिक स्थिरता का फायदा मिला है। इन सभी कैटेगरी में वह पहले स्थान पर है। स्विट्जरलैंड का स्कोर 63.2 रहा है। लिस्ट में कनाडा आठवें (63.2 स्कोर), इटली नौवें (61.6) और संयुक्त अरब अमीरात 59.4 स्कोर के साथ दसवें नंबर पर है। भारत 48.0 के स्कोर के साथ इस फेहरिस्त में 32वें स्थान पर है। यह पिछले साल के मुकाबले दो स्थान नीचे और 1.8 अंक कम है। भारत ने पहचान (13वें), प्रभाव (17वें), और संस्कृति और विरासत (19वें) में मजबूती दिखाई है लेकिन शासन (100वें) और नेट पॉजिटिव प्रभाव (123वें) में भारी गिरावट ने उसे शीर्ष 30 से बाहर कर दिया। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर काफी नीचे 84वां है। इस लिस्ट सबसे निचले पायदान यानी 192 और 193 पर आए देश नारू और किरिबाती हैं। ये दोनों ओशिनिया के देश हैं।

ईरान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में ट्रंप ? परमाणु ठिकानों पर गुप्त हमले और तख्तापलट का प्लान

एजेंसी वॉशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मिलिट्री रेड और स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन शामिल हैं। इसके जरिए ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर हमला किए बगैर तख्तापलट करने और उसके परमाणु महत्वाकांक्षा को खत्म करने पर विचार कर रहा है। अगर इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाता है, तो इसमें ईरानी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी पर तेज हवाई हमले और हाई रिस्क ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए अमेरिकी सैनिकों की खास टुकड़ियां ईरानी जमीन पर उतरेंगी और मिशन अंजाम देकर वापस लौट जाएंगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन जिन योजनाओं पर विचार कर रहा है, इनमें अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज कमांडो को गुप्त रूप से ईरानी इलाके में भेजना और जून 2025 के हमलों के बाद बचे हुए न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करना या उन्हें बेकार करना शामिल है। इसका मकसद ईरान में बड़े पैमाने पर उथल-पुथल पैदा करना है, जिससे देश का मुल्ला सिस्टम अस्थिर हो जाए और संभावित रूप से नेतृत्व परिवर्तन या सत्ता में परिवर्तन जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वह ईरान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वह ईरान से बात कर रहे हैं। उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन से बचने की संभावना को खुला रखा, जबकि पहले चेतावनी दी थी कि तेहरान के लिए समय "खत्म हो रहा है" क्योंकि अमेरिका इस क्षेत्र में एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा भेज रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह ईरान से बात करेंगे, तो ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "मैंने बात की है, और मैं इसकी योजना बना रहा हूं।" ट्रंप ने कहा, कहा, "हमारे पास एक ग्रुप है जो ईरान नाम की जगह पर जा रहा है, और उम्मीद है कि हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा।" ईरान ने भी ट्रंप की धमकियों पर पलटवार किया है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला होता है तो उसे पूर्ण पैमाने पर युद्ध की तरह देखा जाएगा। ईरान ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी भी दी है। ईरानी सेना का कहना है कि वह पहले से ज्यादा तैयार है और उसकी उंगलियां ट्रिगर पर है। एक ईरानी मिलिट्री प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि किसी भी अमेरिकी कार्रवाई पर तेहरान की प्रतिक्रिया सीमित नहीं होगी - जैसा कि पिछले साल जून में हुआ था जब अमेरिकी विमानों और मिसाइलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ईरानी प्रवक्ता ने कहा, "बल्कि यह एक निर्णायक प्रतिक्रिया होगी जो तुरंत दी जाएगी।"

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का `कत्लेआम', 41 बलूचों को मार गिराया, भारत पर लगाया आरोप

एजेंसी इस्लामाबाद

पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में एक सैन्य अभियान के दौरान 41 बलूचों की हत्या कर दी है। पाकिस्तानी सेना के प्रॉपगैंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन (ISPR) ने उन्हें आतंकवादी करार दिया है और उनका संबंध भारत से जोड़ा है। हालांकि, इनके भारत के साथ संबंधों को लेकर कोई भी सबूत नहीं पेश किया है। आईएसपीआर ने दावा किया है कि यह ऑपरेशन बलूचिस्तान के हरनाई और पंजगुर जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की ज्यादती किसी से छिपी नहीं है। इस सूबे के हजारों लोग आज भी अपनों को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें बरसों पहले पाकिस्तानी सेना घरों से पकड़कर ले गई थी।

इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के बयान के अनुसार, "ये ऑपरेशन 29 जनवरी (गुरुवार) को किए गए थे, जिसमें फितना-अल-ख्वारिज और फितना-अल-हिंदुस्तान से जुड़े आतंकवादी मारे गए।" फितना-अल-ख्वारिज एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल राज्य प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े आतंकवादियों के लिए करता है, और फितना-अल-हिंदुस्तान शब्द राज्य द्वारा बलूचिस्तान स्थित समूहों के लिए इस्तेमाल किया गया है ताकि पूरे पाकिस्तान में आतंकवाद और अस्थिरता में भारत की कथित भूमिका को उजागर किया जा सके। ISPR ने कहा, "हरनाई जिले के बाहरी इलाकों में फितना-अल-ख्वारिज की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में एक इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेशन किया गया। बयान में कहा गया है, "ऑपरेशन के दौरान, हमारे सैनिकों ने ठिकाने को प्रभावी ढंग से निशाना बनाया, और भारी गोलीबारी के बाद, भारत समर्थित 30 ख्वारिज को जहन्नुम भेज दिया गया।" ISPR ने दावा किया "आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद हुए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया।" ISPR ने बताया कि उन्हें पंजगुर जिला से भी एक इंटेलिजेंट इनपुट मिला था। इसके बाद सेना ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां 11 बलूचों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने इन्हें भारत समर्थित आतंकवादी करार दिया है। आईएसपीआर ने दावा किया कि दूसरे ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों के पास से 15 दिसंबर, 2025 को पंजगुर में बैंक डकैती में लूटे गए हथियार, गोला-बारूद और पैसे बरामद हुए। ISPR ने आगे कहा, "ये आतंकवादी पहले भी कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे।"

खालिस्तानियों को पालने वाले कनाडा के 2 टुकड़े करने की मांग तेज, अल्बार्टा चाहता है आजादी, मदद करेंगे ट्रंप

एजेंसी वॉशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कनाडा के अलगाववादी संगठन ने आजादी दिलाने की मांग की है। इससे कनाडा आगबबूला हो गया है। ये वही कनाडा है, जो पिछले 50 सालों से खालिस्तानियों को पालता आया है। इसने खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई की भारत की मांग को लगातार खारिज किया है। भला कौन भूल सकता है कि पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कितना बखेड़ा किया था। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने डोनाल्ड ट्रंप से "कनाडाई संप्रभुता का सम्मान करने" का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों ने पिछले अप्रैल से तीन बार एक ऐसे संगठन के नेताओं से मुलाकात की है जो चाहते हैं कि अल्बर्टा प्रांत, कनाडा से अलग हो जाए। अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट नाम का यह ग्रुप अल्बर्टा की आजादी के लिए जनमत संग्रह कराने की मांग कर रहा है। इसके नेता अल्बार्टा की आजादी के लिए अमेरिकी वित्त विभाग से 500 अरब डॉलर का क्रेडिट लाइन मांग रहे हैं।

अल्बर्टा पश्चिमी कनाडा का एक तेल से भरपूर प्रांत है, जो लगभग अमेरिका के टेक्सास जितना बड़ा है। यहां करीब 50 लाख लोग रहते हैं और यह प्रांत रॉकीज पर्वत श्रृंखला और बैनफ और लेक लुईस जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन से घिरा हुआ है। इस प्रांत की एक अनोखी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान है। कनाडा में जितने तेल का उत्पादन होता है, उसका 84 प्रतिशत हिस्सा अल्बार्टा में ही निकलता है। इसीलिए इसे एनर्जी प्रांत भी कहा जाता है। राजनीतिक लिहाजा से इसे कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ माना जाता है, हालांकि इसके शहर क्षेत्र ज्यादा प्रगतिशील हैं। अल्बर्टा की प्रधानमंत्री डेनिएल स्मिथ ट्रंप और दूसरे रिपब्लिकन नेताओं के साथ दोस्ताना रिश्ता रखती हैं। वो पिछले साल जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी आवास मार-ए-लागो भी गईं थीं। माना जा रहा है कि उसके बाद से ही ट्रंप ने अल्बार्टा की आजादी की मांग को हवा देना शुरू कर दिया था।

अल्बर्टा के अलगाववादी समूहों का आरोप है कि ओटावा में उनके हितों का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं होता है। उनका तर्क है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए संघीय सरकार की कोशिशें अल्बर्टा के तेल उद्योग को रोक रही हैं। उनका मानना है कि वो जितना टैक्स चुकाते हैं, उतना अल्बार्टा को वापस नहीं मिलता है। उनके अधिकारियों को कनाडा के पूर्वी प्रांत, जो ज्यादा आबादी वाले हैं, वो दबा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने अप्रैल में 2025 में चुनाव जीतने के लिए एंटी-ट्रंप भावना का खूब फायदा उठाया था, जिसके तुरंत बाद अल्बर्टा विधानमंडल ने एक कानून पास किया, जिससे आजादी पर जनमत संग्रह कराना आसान हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अब इसी को भुना रहे हैं।

अर्जुन तेंदुलकर ने रचा नया कीर्तिमान, पिता सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंचे

अर्जुन तेंदुलकर ने रणजी ट्रॉफी में गोवा के लिए खेलते हुए फर्स्ट-क्लास करियर में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है.

नई दिल्ली, एजेंसी | 'मास्टर-ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर के सुपुत्र, अर्जुन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर में नया मुकाम हासिल कर लिया है. उन्होंने अपने फर्स्ट-क्लास करियर में 50 विकेट पूरे कर लिए हैं. उन्होंने गोवा के लिए खेलते हुए यह कीर्तिमान बनाया है और महाराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में 50वां विकेट चटकाया.

अर्जुन तेंदुलकर एक बाएं हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज हैं, जो जरूरत पड़ने पर बढ़िया बल्लेबाजी शॉट्स भी लगा सकते हैं. उन्होंने साल 2022 के दिसंबर महीने में गोवा के लिए खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ मैच में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. उन्होंने अपने फर्स्ट-क्लास करियर के 23वें मैच में 50 विकेट पूरे किए हैं. वो रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में गोवा के लिए खेलते हुए 13 विकेट ले चुके हैं.

पिता का रिकॉर्ड तोड़ेंगे!

अर्जुन अभी फर्स्ट-क्लास करियर में विकेट लेने के मामले में अपने पिता, सचिन तेंदुलकर से 21 विकेट पीछे हैं. सचिन ने अपने फर्स्ट-क्लास करियर में 71 विकेट लिए थे. अर्जुन का डोमेस्टिक करियर अलग और खास रहा है. अर्जुन डोमेस्टिक क्रिकेट करियर की शुरुआत में मुंबई के लिए खेला करते थे, वो आज गोवा टीम में ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आते हैं.

आपको बताते चलें कि अर्जुन तेंदुलकर इंडियन प्रीमियर लीग में कई सीजन तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे, लेकिन IPL 2026 में उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने साथ जोड़ लिया है.

अर्जुन तेंदुलकर का करियर

अर्जुन तेंदुलकर अब तक 23 मैचों के फर्स्ट-क्लास करियर में 50 विकेट लेने के अलावा 625 रन भी बना चुके हैं. रेड बॉल क्रिकेट में उनके बल्ले से एक शतक और 2 अर्धशतकीय पारियां भी निकली हैं. वहीं 24 मैचों के लिस्ट-A करियर में उनके नाम 26 विकेट हैं. वहीं अपने टी20 करियर में अर्जुन तेंदुलकर ने 29 मैच खेलकर 25 विकेट चटकाए हैं.

मध्यप्रदेश क्वार्टर फाइनल में, सौराष्ट्र क्वालीफिकेशन के करीब

इंदौर, एजेंसी | बायें हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय के शानदार प्रदर्शन से मध्यप्रदेश ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी के अपने आखिरी लीग मैच में तीसरे दिन शनिवार को महाराष्ट्र को 133 रन से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सौराष्ट्र ने भी चंडीगढ को एक पारी और 56 रन से हराकर दूसरा स्थान हासिल कर लिया और उसका क्वालीफिकेशन तय है । अगर रविवार को मोहाली में कर्नाटक पंजाब को हरा देता है तो ही सौराष्ट्र बाहर होगा । तीसरे दिन चार विकेट पर 166 रन से आगे खेलते हुए मध्यप्रदेश की टीम 76 . 1 ओवर में 258 रन पर आउट हो गई जिससे महाराष्ट्र को 267 रन का लक्ष्य मिला ।

शुभम शर्मा ने 90 रन बनाये जबकि सारांश जैन (23) और कार्तिकेय (20) ने भी योगदान दिया । सागर सोलंकी अपने कल के स्कोर में चार रन जोड़कर आउट हो गए । जवाब में महाराष्ट्र की टीम 36 ओवर में 133 रन पर आउट हो गई । पहली पारी में छह विकेट लेने वाले कार्तिकेय ने 49 रन देकर चार विकेट लिये । मध्यम तेज गेंदबाज आर्यन पांडे को भी चार विकेट मिले। वहीं बायें हाथ के स्पिनर धर्मेंद्रसिंह जडेजा और मध्यम तेज गेंदबाज चिराग जानी के चार चार विकेट की मदद से सौराष्ट्र ने चंडीगढ को 261 रन पर आउट करके एक पारी और 56 रन से जीत दर्ज की ।

सौराष्ट्र ने पहली पारी तीन विकेट पर 453 रन पर घोषित की थी । चंडीगढ ने पहली पारी में 136 रन बनाये थे । वहीं नॉकआउट में जगह बनाने के लिये जीत के प्रयास में जुटी कर्नाटक के खिलाफ पंजाब ने तीन विकेट पर 119 रन बना लिये । कर्नाटक ने पहली पारी में 316 रन बनाये थे। मैच में एक ही दिन बाकी है और कोई नतीजा आने के लिये कर्नाटक को चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा ।

तीसरा सबसे बड़ा टी20 स्कोर बनाने के बाद 46 रनों से जीता भारत, ईशान का शतक फिर अर्शदीप ने मारा पंजा

भारत ने पांचवां टी20 मैच 46 रनों से जीत लिया है. ईशान किशन ने शतक और गेंदबाजी में भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लिए. भारत ने सीरीज 4-1 से जीती

नई दिल्ली, एजेंसी | भारत ने पांचवां टी20 मैच 46 रनों से जीत लिया है. तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया था. ये अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 225 रनों पर ऑलआउट हो गई. इसी के साथ भारत ने यह सीरीज 4-1 से जीत ली है.

टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. संजू सैमसन एक बार फिर फ्लॉप रहे, जो केवल 6 रन बना पाए. अभिषेक शर्मा अपनी 16 गेंद में 30 रन की पारी को अर्धशतक या शतक में तब्दील नहीं कर पाए.

अर्शदीप सिंह ने मारा पंजा

अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. 100 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, जब उन्होंने एक ही मैच में 5 विकेट लिए हों. न्यूजीलैंड के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में उन्होंने 4 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट लिए. अर्शदीप इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे. उन्होंने सीरीज में 8 विकेट लिए.

ईशान किशन का 42 गेंद में शतक

ईशान किशन ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 42 गेंदों में शतक पूरा किया. उन्होंने इस मैच में 43 गेंद खेलकर 103 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 6 चौके लगाए. ये अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में भारत के लिए पांचवां सबसे तेज और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में सबसे तेज शतक रहा.

भारत ने 4-1 से जीती सीरीज

टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया है. पहला टी20 मैच नागपुर में खेला गया, जिसे भारत ने 41 रनों से जीता था. उसके बाद टीम इंडिया ने 7 विकेट और फिर गुवाहाटी में 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. सीरीज में न्यूजीलैंड की एकमात्र जीत चौथे मैच में आई, जो विशाखापट्टनम में खेला गया. न्यूजीलैंड ने वह मुकाबला 50 रनों से जीता था. अब पांचवें मैच में टीम इंडिया ने वापसी करते हुए 46 रनों से जीत प्राप्त की.

एलेना रिबाकिना बनीं ऑस्ट्रेलियन ओपन की नई चैंपियन, रोमांचक फाइनल में आर्यना सबालेंका को दी मात

एलेना रिबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के फाइनल में विश्व नंबर 1 आर्यना सबालेंका को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया और अपना पहला खिताब जीता। इस रोमांचक तीन-सेट की जीत के साथ, रिबाकिना ने 2023 के फाइनल में सबालेंका से मिली हार का बदला भी पूरा कर लिया।

नई दिल्ली, एजेंसी | एलेना रिबाकिना ने शनिवार, 31 जनवरी को रॉड लेवर एरिना में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सबलेंका को 6-4, 4-6, 6-4 से हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता और अपनी हार का बदला पूरा किया। 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में सबलेंका से मिली हार का बदला लेने की कोशिश कर रही रिबाकिना ने पहले सेट में शानदार खेल दिखाया और सबलेंका को दबाव में रखा। उन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी की सर्विस तोड़ते हुए उन्हें एक भी ब्रेक नहीं लेने दिया और पहला सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में भी दोनों आ क्रा म क खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी, जबकि स ब लें का ने अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश की। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सर्विस बचाए रखी, लेकिन दूसरे सेट में सबसे अहम मौके पर सबलेंका को एक ब्रेक मिल गया। 5-4 के स्कोर पर, सबलेंका को तीन ब्रेक प्वाइंट मिले और उन्होंने पहला ब्रेक प्वाइंट भुनाकर स्कोर बराबर कर दिया। तीसरा सेट भी दोनों खिलाड़ियों के बीच एक रोमांचक मुकाबला था, जिन्होंने 2023 में मेलबर्न पार्क में भी खिताब के लिए संघर्ष किया था। शीर्ष वरीयता प्राप्त सबालेंका ने अपनी सर्विस बचाकर शुरुआत की और फिर पांचवीं वरीयता प्राप्त रिबाकिना की सर्विस को एक शानदार बैकहैंड शॉट से तोड़ दिया। लेकिन कजाख खिलाड़ी ने भी अपनी सर्विस तोड़कर स्कोर 3-3 कर दिया।

निर्णायक सेट में रिबाकिना ने एक बार फिर सर्विस तोड़कर सबालेंका को 4-3 से पीछे कर दिया, जिससे सबालेंका दबाव में आ गईं। शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को मैच जीतने के लिए लगभग चमत्कार की जरूरत थी। हालांकि सबालेंका ने अपनी सर्विस बचा ली, लेकिन वह कजाख खिलाड़ी की सर्विस नहीं तोड़ सकीं और रायबाकिना ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया। रिबाकिना की जीत में कई रिकॉर्ड भी शामिल थे। वह मारिया शारापोवा के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीतने के रास्ते में शीर्ष छह खिलाड़ियों में से तीन को हराने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं।

व्यापार

केंद्रीय बजट 2026 के बाद युवा शक्ति से चर्चा करेंगी निर्मला सीतारमण

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 कॉलेज विद्यार्थियों से संवाद करेंगी, जिसका उद्देश्य युवाओं को बजट प्रक्रिया की सीधी जानकारी देना और आर्थिक नीतियों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

नई दिल्ली, एजेंसी | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को आम बजट 2026-27 पेश करने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 30 कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगी। सीतारमण एक फरवरी को अपना रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करने जा रही हैं, जिसमें दो अंतरिम बजट भी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस पहल के तहत छात्र-छात्राओं को लोकसभा दीर्घा से केंद्रीय बजट पेश किए जाने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलेगा।

इससे वे वर्ष की इस सबसे महत्वपूर्ण संसदीय कार्यवाही के साक्षी बन सकेंगे। बयान के अनुसार, ये छात्र भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं और वाणिज्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शिक्षा तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे विभिन्न शैक्षणिक विषयों से जुड़े हैं। ये छात्र कर्तव्य भवन-1 स्थित वित्त मंत्रालय भी जाएंगे और वहां के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य उन्हें मंत्रालय के कामकाज, नीतियों के निर्धारण की प्रक्रिया और राष्ट्र निर्माण में संस्थानों की भूमिका के बारे में व्यावहारिक समझ प्रदान करना है।

शाम को वित्त मंत्री सीतारमण छात्र-छात्राओं के साथ एक मुक्त चर्चा करेंगी। इस दौरान बजट की मुख्य प्राथमिकताओं, भारत के भविष्य के दृष्टिकोण और युवाओं पर इसके प्रभावों पर चर्चा होगी। छात्र भी इस संवाद के दौरान अपने विचार, आकांक्षाएं और राष्ट्र के प्रति अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। मंत्रालय के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच वित्त, अर्थशास्त्र, शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

साथ ही, यह भारत की वित्तीय और संसदीय कार्यवाहियों में युवाओं की रचनात्मक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। बयान में यह भी कहा गया है कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मंचों के माध्यम से युवाओं सहित आम नागरिकों से सुझाव मांगे गए थे, जिनकी झलक आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 में दिखाई देगी।

ब्रह्मोस का उन्नयन एक निरंतर चलने वाली परियोजना : रूसी साझेदार

नई दिल्ली, एजेंसी | ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली परियोजना है, जिसका उद्देश्य हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ना है। रूस के संयुक्त उद्यम (जेवी) साझेदार के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्नत मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणालियों से लैस ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या जमीन से प्रक्षेपित किया जा सकता है।

रूसी संयुक्त उद्यम साझेदार 'एनपीओ माशिनोस्ट्रोयेनिया' के मुख्य कार्यपालक अ धि का री (सीईओ) और मुख्य डिजाइनर अ ले क जें ड र लियोनोव ने शुक्रवार को अंतरिक्ष विज्ञान (कॉस्मोनॉटिक्स) पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि रूस और भारत संयुक्त रूप से उत्पादित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को लगातार उन्नत कर रहे हैं और हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी 'तास' के अनुसार लियोनोव ने कहा, 'हम इन मिसाइलों का लगातार आधुनिकीकरण कर रहे हैं और इनकी विशेषताओं में सुधार कर रहे हैं। इसीलिए यह एक निरंतर चलने वाला कार्य है। ब्रह्मोस परियोजना के तहत छोटे आकार की मिसाइलों और हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों पर भी काम चल रहा है।'

Q3 Results में PSU Banks का जलवा, अब Budget 2026 से बड़ी उम्मीदें, जानें आगे क्या होगा?

वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में PSU बैंकों ने 56% तक की मुनाफा वृद्धि के साथ शानदार प्रदर्शन किया है, जिसका मुख्य कारण NPA में कमी और बेहतर नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है। यह प्रदर्शन आर्थिक सुधार का संकेत है और आगामी बजट से बैंकिंग सेक्टर को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली, एजेंसी | भारतीय बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) सेक्टर के लगातार बदलते परिदृश्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Banks) ने वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (Q3) में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा है। मुनाफे में 56% तक की जोरदार बढ़त के साथ, ये बैंक निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों के लिए चर्चा का केंद्र बन गए हैं। यह लेख प्रमुख PSU बैंकों के मजबूत वित्तीय नतीजों, हालिया शेयर बाजार तेजी के प्रभाव और आगामी बजट दिवस से जुड़ी संभावनाओं पर विस्तार से नजर डालता है।

Q3 नतीजेः मुनाफे में मजबूत उछाल - तीसरी तिमाही के नतीजों ने कई PSU बैंकों के लिए सकारात्मक तस्वीर पेश की है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो महामारी के बाद आर्थिक सुधार का स्पष्ट संकेत है। देश के सबसे बड़े PSU बैंक SBI ने साल-दर-साल आधार पर 56% की जबरदस्त मुनाफा वृद्धि दर्ज की, जिसका मुख्य कारण खराब ऋणों में कमी और बेहतर नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा।

वहीं, केनरा बैंक ने 40% से अधिक की मुनाफा बढ़त के साथ अपने मजबूत कारोबारी मॉडल और प्रभावी प्रबंधन की झलक दिखाई। बैंक ऑफ बड़ौदा भी पीछे नहीं रहा और उसने 37% की लाभ वृद्धि दर्ज कर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों में अपनी जगह बनाई। इन नतीजों से साफ है कि PSU बैंक बदलते बाजार हालात के अनुरूप खुद को ढालने में सक्षम रहे हैं।

मुनाफा बढ़ने के पीछे के प्रमुख कारण - Q3 में PSU बैंकों के शानदार प्रदर्शन के पीछे कई अहम कारण रहे हैं। सबसे बड़ा कारण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में आई गिरावट है, जिससे बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत हुई और लाभप्रदता में सुधार आया। बेहतर एसेट क्वालिटी के चलते बैंक न सिर्फ पुराने कर्ज की बेहतर वसूली कर पा रहे हैं, बल्कि विकास से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स में भी निवेश कर रहे हैं।

इसके अलावा, बढ़ती ब्याज दरों ने भी बैंकों की नेट इंटरेस्ट इनकम को सहारा दिया है। ऋण पर ऊँची दरें और जमा पर प्रतिस्पर्धी ब्याज बनाए रखने से मार्जिन में सुधार हुआ, जिसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ा।

शेयर बाजार तेजी की भूमिका - हालिया शेयर बाजार तेजी ने PSU बैंक शेयरों की आकर्षण क्षमता को और मजबूत किया है। सकारात्मक बाजार धारणा के बीच निवेशक इन शेयरों में पूंजी लगा रहे हैं, जिससे इनके दाम और मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा हुआ है। यह तेजी आर्थिक सुधार, सरकारी सुधारों और कारोबार के विस्तार के साथ बढ़ती ऋण मांग की उम्मीदों से प्रेरित है।

रिकवरी के इस दौर में निजी बैंकों की तुलना में PSU बैंकों के मजबूत प्रदर्शन ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। खुदरा और संस्थागत दोनों निवेशकों की ओर से खरीदारी बढ़ने से इन शेयरों में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है।

बजट दिवस का असरः आगे क्या उम्मीद? - बजट दिवस के करीब आते ही PSU बैंकों पर सरकार की वित्तीय नीतियों का असर खासा महत्वपूर्ण रहेगा। निवेशकों को उम्मीद है कि सरकार बैंकिंग सेक्टर को मजबूती देने के लिए पूंजी निवेश, ऋण प्रोत्साहन और वित्तीय समावेशन से जुड़े कदम उठा सकती है।

यूएस फ्रॉड केस में गौतम अडानी का बड़ा कदम, एसईसी का नोटिस स्वीकारा, अब 90 दिनों में देंगे जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी | अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने धोखाधड़ी के एक दीवानी मामले में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) से कानूनी नोटिस स्वीकार करने पर सहमति जताई है। इससे एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक बाधा दूर हो गई है और न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित संघीय अदालत में मामले की कार्यवाही आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अदालती दस्तावेज़ के अनुसार, अडानी के वकील न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले की अदालत में पेश हुए और अपने मुवक्किलों की ओर से एसईसी का समन स्वीकार करने पर सहमति दी। अदालत ने कहा कि हालांकि उन्होंने नोटिस स्वीकार करने पर सहमति जताई है, लेकिन प्रतिवादियों ने क्षेत्राधिकार सहित सभी आधारों पर मामले को चुनौती देने का अधिकार स्पष्ट रूप से सुरक्षित रखा है। अदालत के निर्देशों के अनुसार, गौतम और सागर अदानी के पास अब एसईसी की शिकायत पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय है। नियामक के पास आवश्यकता पड़ने पर जवाब दाखिल करने के लिए 60 दिन तक का समय होगा, जिसके बाद प्रतिवादी आगे के जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह मामला गौतम और सागर अदानी पर लगे उन आरोपों से जुड़ा है कि उन्होंने अदानी ग्रीन एनर्जी के भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों से संबंधित रिश्वतखोरी योजना के बारे में अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया, जो अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों और विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन है।

एसईसी ने शुरू में नवंबर 2024 में मुकदमा दायर किया था। मामले में एक साल से अधिक की देरी हो गई थी, क्योंकि प्रतिवादी भारत में ही थे और उन्हें नोटिस नहीं भेजा जा सका था। पिछले सप्ताह, एसईसी ने भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से नोटिस भेजने के प्रयास विफल होने के बाद अमेरिकी वकील और व्यावसायिक ईमेल के माध्यम से वैकल्पिक नोटिस भेजने का अनुरोध किया।

अदानी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा शाखा, एजीईएल ने दावा किया है कि कंपनी इस कार्यवाही में पक्षकार नहीं है। कार्यवाही में केवल कंपनी के दो निदेशक ही पक्षकार हैं। हालांकि, निदेशकों के खिलाफ कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाए गए हैं। कार्यवाही पूरी तरह से दीवानी प्रकृति की है। गौतम और सागर अदानी ने अपने बचाव के लिए वॉल स्ट्रीट के जाने-माने वकील रॉबर्ट गिफ्रा जूनियर को नियुक्त किया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित कई हाई-प्रोफाइल ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रसिद्ध हैं। गिफ्रा ने प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार करने के समझौते की पुष्टि की, जिससे अदालत को नोटिस प्रक्रिया पर निर्णय लेने की आवश्यकता के बिना मामला आगे बढ़ सकेगा। एसईसी का मामला अब औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़ेगा। अदानी परिवार मामले को खारिज करने के लिए याचिका या जवाब दाखिल कर सकता है, जबकि नियामक को उठाए गए किसी भी बचाव का विरोध करने का अधिकार होगा।

मनीष पॉल की शादी को पूरे हुए 19 साल, पत्नी के नाम लिखा भावुक नोट

एक्टर और टेलीविजन होस्ट मनीष पॉल के लिए आज का दिन बेहद खास है. मनीष और उनकी पत्नी संयुक्ता पॉल ने अपनी शादी के 19 साल पूरे कर लिए हैं. लगभग दो दशकों के प्यार, साथ और अटूट भरोसे का जश्न मनाते हुए मनीष पॉल ने सोशल मीडिया पर पत्नी के नाम एक भावुक नोट के साथ अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी पोस्ट की हैं. अपने इमोशनल पोस्ट में मनीष पॉल ने शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई को बेहद खूबसूरती से बयां किया है, जहां उतार-चढ़ाव, समझौता, दोस्ती और बिना शर्त साथ निभाने की भावना शामिल होती है. मनीष का यह पोस्ट फैंस के दिल को छू गया. इसके बाद कमेंट सेक्शन में बधाइयों, प्यार और तारीफों की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भागदौड़ भरी जिंदगी के बावजूद अपने रिश्ते को मजबूती से निभाने के लिए इस जोड़ी की सराहना भी की है.मनीष और संयुक्ता पॉल को लंबे समय से उनकी सादगी भरे रिश्ते और लाइमलाइट से दूर बैलेंस्ड पर्सनल लाइफ जीने के लिए जाना जाता रहा है. हालांकि मनीष कई बार पब्लिकली ये कह भी चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी और करियर में संयुक्ता उनका सबसे बड़ा सहारा और ताकत रही हैं. चाहे प्रोफेशनल उतार-चढ़ाव हो या निजी चुनौतियां, संयुक्ता हमेशा उनके साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रही हैं. शादी के 19 साल पूरे करने पर मनीष और संयुक्ता की यह यात्रा इस बात की खूबसूरत मिसाल है कि सच्चा प्यार समय के साथ और गहरा होता है।

7 एपिसोड की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सिर्फ इंडिया नहीं, विदेशों में भी बनी नंबर 1

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी पहली सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बीते साल सितंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. 7 एपिसोड की इस सीरीज ने आते ही नेटफ्लिक्स पर कब्जा कर लिया था और खूब ट्रेंड कर रही थी. 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद et देखने वालों को एक नया जुनून मिल गया है. इन दिनों नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज इतना धमाल मचा रही है कि इसने आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को भी व्यूअरशिप के मामले में पीछे छोड़ दिया है. इस सीरीज को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है और इसलिए ये वेब सीरीज लवर्स के लिए मस्ट वॉच बन गई है.अब ये et की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश सीरीज बन गई है. ये सीरीज कोई और नहीं, बल्कि इमरान हाशमी की हालिया रिलीज 'तस्करी' है. इमरान हाशमी की 'तस्करी' 14 जनवरी को ह्रअ्र पर रिलीज हुई और ये देखते ही देखते नेटफ्लिक्स के टॉप 10 नॉन-इंग्लिश शो की वर्ल्ड लिस्ट में टॉप पर पहुंच गई।

बिजनेस में कैटरीना हैं नंबर वन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को उनकी खूबसूरती और हिट फिल्मों के साथ ही एक सफल बिजनेस वूमन के रूप में भी जाना जाता है। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए कैटरीना को भाषा से लेकर एक्टिंग स्किल्स तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज कैटरीना सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस ही नहीं हैं, बल्कि बेहद सेक्सेसफुल बिजनेस वूमन भी है। इस ब्रांड की सफलता के मामले में भी वे बाकी एक्ट्रेसेस से काफी आगे हैं।

साल 2019 में कैटरीना ने अपना ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' लॉन्च किया। कैटरीना ने अपने ब्रांड की शुरुआत पूरी रणनीति के साथ की। सबसे पहले उन्होंने साल 2018 में रिटेल कंपनी नायका के साथ एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें कैटरीना ने करीब 2.04 करोड़ रुपए निवेश किए। साल 2021 तक यह निवेश बढ़कर करीब 22 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस निवेश से कैटरीना के आगे की बिजनेस का बेस तैयार हुआ। साल 2019 में उन्होंने नायका के साथ मिलकर ब्रांड 'के ब्यूटी' की स्थापना की। आज यह ब्रांड महिलाओं की पसंद बना हुआ है।

मेकअप में बचपन से रुचि

कैटरीना ने अपने कई इंटरव्यूज में यह बताया है कि उन्हें बचपन से ही मेकअप में रुचि है। यही कारण था कि एक्टिंग में करियर बनने के साथ ही उन्होंने ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया। हालांकि कैटरीना कैफ अकेली नहीं हैं, जिन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। इस लिस्ट में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से लेकर कृति सनोन और मीरा राजपूत का भी नाम शामिल है। हालांकि सफलता के मामले में कैटरीना सबसे आगे हैं।

और आज बना बड़ा ब्रांड

आज 15 लाख से ज्यादा कस्टमर 'के ब्यूटी' के पोर्टफोलियो में शामिल हैं। कंपनी ने करीब 62 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है।स्टोरीबोर्ड-18 की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में 'के ब्यूटी' ने करीब 240 करोड़ रुपए रेवेन्यू अर्जित किया है। दूसरी ओर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का ब्यूटी ब्रांड 82एई साल 2024 में करीब 25 करोड़ रुपए के घाटे में बताया जा रहा है। वहीं एक्ट्रेस कृति सनोन ने यूथ की जरूरतों को समझकर स्किनकेयर ब्रांड 'हाइफन' लॉन्च किया। इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस ब्रांड ने अपने पहले ही साल में 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाया। हालांकि इसके बावजूद कंपनी साल 2023-24 में करीब 25 लाख रुपए के घाटे में रही।ब्यूटी ब्रांड के अलावा कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने फैशन ब्रांड्स भी लॉन्च कर रखे हैं। इनमें ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के आसपास कोई नहीं पहुंच पाया है। ऋतिक ने साल 2013 में फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड 'एचआरएक्स' को लॉन्च किया था। अपने स्टाइलिश और बजट फ्रेंडली कपड़ों व अन्य एक्सेसरीज के कारण इस ब्रांड को लोगों का भरपूर प्यार मिला। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एचआरएक्स ने करीब 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली के क्लोदिंग ब्रांड ड्ढह्रतह्र की आय में करीब 29 प्रतिशत की कमी आई है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के ब्रांड नुश, सोनम कपूर का ब्रांड रीजन, शाहिद कपूर का ब्रांड स्कल्ट, सभी मुनाफा कमाने की दौड़ में काफी पिछड़ी हुई हैं।

रानी मुखर्जी के बयान पर भड़के लोग

बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में घरेलू रिश्तों और जेंडर रोल्स को लेकर अपने विचार रखे, जो अब सोशल मीडिया पर बहस का बड़ा मुद्दा बन गए हैं। रानी ने कहा कि पत्नियों को अपने पतियों से बात करते समय अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें आवाज़ ऊंची क्यों न करनी पड़े। उनका यह बयान सामने आते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई सोशल मीडिया यूज़र्स का कहना है कि इस तरह की बातें वैवाहिक रिश्तों में चिल्लाने या आक्रामक व्यवहार को सामान्य बनाती हैं।

'सम्मान की शुरुआत घर से होती है'

इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने कहा कि किसी भी बच्चे, खासकर लड़के के व्यक्तित्व और सोच पर उसके पिता के व्यवहार का गहरा असर पड़ता है। अगर कोई लड़का अपनी मां को अपमानित होते हुए देखता है, तो उसके भीतर यह धारणा बन जाती है कि अगर मेरी मां के साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी भी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार किया जा सकता है। पिता को यह समझना चाहिए कि वे घर में अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा वही देखकर बड़ा होता है। अगर मां को सम्मान मिलता है, तो बेटा भी यही सीखता है कि महिलाओं को समाज में सम्मान और बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए।

विवाद की जड़ बना बयान

इसी बातचीत के दौरान रानी ने कहा कि पिता का मां पर आवाज़ उठाना बिल्कुल सही नहीं है। बल्कि मां को पिता पर आवाज़ उठानी चाहिए, यही सही तरीका है।इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने इसे महिलाओं को अपनी बात मजबूती से रखने का संदेश बताया, जबकि बड़ी संख्या में यूज़र्स ने कहा कि इस बयान से रिश्तों में चिल्लाने जैसे व्यवहार को जायज़ ठहराया जा रहा है।इंटरव्यू के दौरान रानी मुखर्जी ने अपने स्कूल के दिनों की एक घटना भी साझा की। उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने एक बार एक लड़के को थप्पड़ मारा था। इस किस्से को सुनाते हुए रानी ने मज़ाकिया अंदाज़ में अपने पति, फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा का भी ज़िक्र कर दिया।रानी ने हंसते हुए कहा, मैंने सिर्फ एक ही लड़के को थप्पड़ मारा था, बाकी सारे मेरे दोस्त थे।

अल्लू अर्जुन की 23वीं फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर को किया गया अप्रोच

बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बीच बढ़ते मेल-जोल के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दीपिका पादुकोण के बाद अब श्रद्धा कपूर का नाम साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ जोड़ा जा रहा है। बी-टाउन के सूत्रों की मानें तो अल्लू अर्जुन की 23वीं फिल्म 23 के लिए श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया गया है। हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि मेकर्स एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश में हैं, जिसकी पैन-इंडिया अपील हो और जो साउथ व नॉर्थ, दोनों ऑडियंस से कनेक्ट कर सके। श्रद्धा कपूर इस क्राइटेरिया पर पूरी तरह फिट बैठती हैं। उनकी पिछली फिल्मों और पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स उन्हें एक मजबूत विकल्प मान रहे हैं। अगर यह कास्टिंग फाइनल होती है, तो यह श्रद्धा कपूर का साउथ सिनेमा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। वहीं, अल्लू अर्जुन के फैंस भी इस संभावित फ्रेश जोड़ी को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अब सभी की नजरें मेकर्स की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, जिससे इस खबर पर मुहर लग सके।

खाद वितरण में पारदर्शिता के लिए ई-विकास प्रणाली लागू, अब किसान अब घर बैठे बुक कर सकेंगे ई-टोकन

• साधना एक्सप्रेस, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, किसानों की सुविधा के लिए उर्वरक वितरण ई-विकास प्रणाली लागू की गई है। इस नई व्यवस्था से अब किसानों को खाद (उर्वरक) प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना होगा और मोबाईल व कियोस्क सेंटर के माध्यम से वे अपना ई-टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

ई-विकास प्रणाली में ई-टोकन प्राप्त करने के लिए किसान ई-विकास प्रणाली पोर्टल etoken.mpkrishi.org पर अपने आधार नंबर और मोबाइल ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीयन होते ही पोर्टल में स्वतः ही 'AgriStack' के माध्यम से किसान की भूमि की जानकारी प्रदर्शित हो जायेगी। किसानों को प्रदर्शित भूमि की जानकारी के अनुसार खसरा अनुसार बोई गई फसलों की जानकारी स्वयं ही दर्ज करनी होगी। भूमि के रकबे एवं दर्ज की गई फसल की जानकारी के आधार पर पोर्टल स्वतः ही वैज्ञानिक अनुशंसा अनुसार उर्वरक की गणना कर किसान को आवश्यक कुल उर्वरक की मात्रा प्रदर्शित हो जायेगी। प्रदर्शित उर्वरक की मात्रा अनुसार किसान अपनी सुविधा अनुसार नजदीकी खाद विक्रय केंद्र (जिला विपणन केन्द्र, मार्केटिंग सोसाइटी, सहकारी समितियों, एमपी एग्रो या निजी विक्रेता) का चयन कर डिजिटल ई-टोकन जनरेट कर सकेंगे। किसान यह भी चयन करेंगे कि वे सहकारी समिति के सदस्य है कि नहीं। यदि वे सहकारी समिति के सदस्य है तो वे सहकारी समितियों का विकल्प चयन कर ई-टोकन प्राप्त कर सकेंगे। जबकि, सहकारी समिति के सदस्य न होने की दशा में नहीं का चयन कर अन्य नगद उर्वरक विक्रेताओं (जिला विपणन केन्द्र, मार्केटिंग सोसाइटी, एमपी एग्रो या निजी विक्रेता) का चयन कर ई-टोकन जनरेट कर सकेंगे।

ई-टोकन जनरेट होने के बाद किसान को निर्धारित तिथि से 3 दिन (अवकाश दिवसों को छोड़कर) के भीतर खाद

उठाना अनिवार्य है। 3 दिन उपरांत खाद न लेने पर ई-टोकन स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं किसान पुनः ई-टोकन जनरेट कर खाद प्राप्त कर सकेंगे। पात्रता अनुसार एक किसान एक माह में अधिकतम 50 बोरी उर्वरक प्राप्त कर सकता है। दोबारा खाद की आवश्यकता होने पर 30 दिन के अंतराल के बाद ही अगला टोकन बुक किया जा सकेगा। जिन किसानों (ट्रस्ट, पट्टा या सिकमी एवं अन्य) पंजीकरण करने के बाद भी भूमि की जानकारी का डेटा पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, वे कृषक पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपनी खसरा अनुसार जानकारी दर्ज करेगें। इसका सत्यापन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) द्वारा किया जावेगा। तत्पश्चात कृषक अपना टोकन जनरेट कर सकेगें।

उपसंचालक कृषि ने बताया कि ई-विकास प्रणाली से खाद की कालाबाजारी और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त होगी। रीयल-टाइम डेटा के माध्यम से उर्वरक की मांग और आपूर्ति पर सटीक नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विदिशा, जबलपुर और नर्मदापुरम जैसे जिलों में इसके सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। जहाँ हजारों किसानों को बिना किसी असुविधा के खाद उपलब्ध कराई गई है। ई-विकास प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक किसान तक समय पर और पारदर्शी तरीके से उर्वरक पहुंचाना सुनिश्चित किया जायेगा।

मां त्रिनेत्री गौशाला बहोरीपार का निरीक्षण

नरसिंहपुर, कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के निर्देशानुसार और सीईओ जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में उप संचालक कृषि श्री मोरिस नाथ एवं परियोजना संचालक आत्मा श्री आरपी झारिया ने बहोरीपार में मां त्रिनेत्री गौशाला का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान गौशाला में उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। अधिकारियों द्वारा वर्मीपिट हेतु शेड निर्माण, तालाब निर्माण, स्ट्रारीपर इकाई, प्राकृतिक सब्जी उत्पादन, जैविक कीटनाशक इकाई, बायोफ्लाक मछली पालन यूनिट, गोबर से लकड़ी एवं दीया निर्माण जैसी गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए।

इन नवाचारों से गौशाला की आय में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावनाएं भी व्यक्त की गईं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता एवं फिजिकल क्लास का आयोजन

नरसिंहपुर, . बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासकीय महिला महाविद्यालय नरसिंहपुर स्थित ग्राउंड पर बालिका क्रिकेट मैच सह फिजिकल क्लास का आयोजन किया गया।

आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में सीनियर बालिका टीम एवं जूनियर बालिका टीम के मध्य मुकाबला संपन्न हुआ। सीनियर टीम की कप्तानी सुश्री अंजलि दीक्षित एवं जूनियर टीम की कप्तानी सुश्री रश्मि चौधरी द्वारा की गई। सीनियर टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 7 विकेट खोकर 64 रन बनाए। टीम की ओर से सर्वाधिक 18 रन छात्रा सुश्री शिखा लोधी ने बनाए।

64 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जूनियर टीम 6 ओवर में 28 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जूनियर टीम की ओर से सर्वाधिक 8 रन छात्रा सुश्री प्रियंका ठाकुर ने बनाए। प्रतियोगिता में पुरस्कार स्वरूप सभी प्रतिभागी छात्राओं को स्टेशनरी सामग्री प्रदान की गई।

मैच में अंपायरिंग की भूमिका बाल संरक्षण अधिकारी श्री सौनिध्य सराठे एवं श्री आशीष विश्वकर्मा द्वारा निभाई गई। सर्वाधिक 18 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सुश्री शिखा लोधी को जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास नरसिंहपुर श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही दोनों टीमों की कप्तान सुश्री अंजलि दीक्षित एवं सुश्री रश्मि चौधरी को भी पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक पद की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्रा सुश्री प्रिया नामदेव को भी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया तथा आगामी फिजिकल परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर महिला सशक्त वाहिनी क्लास के अंतर्गत जानकारी दी गई कि कक्षा 12 उत्तीर्ण इच्छुक छात्राएं निःशुल्क पंजीयन कर फिजिकल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। चयनित छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाएगी। इस कक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक छात्राओं का पुलिस भर्ती में चयन सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम के अंत में छात्राओं द्वारा ट्रैक शूट पर बने बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ के मोनो के माध्यम से जन-जागरूकता संदेश दिया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राधेश्याम वर्मा ने छात्राओं को मन लगाकर अध्ययन करने एवं लक्ष्य पर केंद्रित रहने की प्रेरणा दी।

ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान अंतर्गत रोसरा ग्राम पंचायत में ग्रामोत्सव कार्यक्रम संपन्न

नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद नरसिंहपुर के तत्वाधान में नवांकुर संस्था जय ज्वाला शिक्षा एवं प्रचार-प्रसार समिति नरसिंहपुर के नेतृत्व में तथा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति रोसरा एवं ग्राम पंचायत रोसरा के सहयोग से ग्रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कुसुम वैली के सभागार में संपन्न हुआ।

जिला समन्वयक श्री जयनारायण शर्मा ने कहा कि ग्राम विकास के माध्यम से राष्ट्र विकास की परिकल्पना को साकार करने हेतु स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। श्री शर्मा ने बताया कि यह अभियान राज्य शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र हितग्राहियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक नागरिक योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत पौधारोपण, जल संचय, प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली, नशामुक्ति, शिक्षा एवं संस्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग जैसे विषयों में सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री संजय खरे ने ग्राम स्वच्छता, सबके लिए स्वास्थ्य- सबके लिए शिक्षा एवं संस्कार के साथ-साथ जैविक कृषि एवं जैविक उत्पादों के उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीणजनों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति रोसरा के श्री ओंकार प्रताप पटेल द्वारा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सौर ऊर्जा के उपयोग, जल संचय तथा साइकिल को पर्यावरण हितैषी एवं स्वास्थ्यवर्धक साधन के रूप में अपनाने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय श्री ओंकार प्रताप पटेल द्वारा किया गया। ग्रामोत्सव कार्यक्रम में मप्र जनअभियान परिषद की संस्थाओं के पदाधिकारी और ग्रामीणजन मौजूद रहे

रबी विपणन वर्ष 2026- 27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च तक किया जाएगा

नरसिंहपुर, राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के द्वारा जारी निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2026- 27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक किया जाएगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि भूमि स्वामी, सिकमी/ बटाईदार/ कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन की प्रकिया, डाटा संशोधन एवं पंजीयन सत्यापन के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। सिकमी/ बटाईदार किसानों का पंजीयन कराने के लिए मूल भूमि स्वामी, सिकमी/ बटाईदार किसानों की बीच मप्र भूमि स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक 2016 की कंडिका के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध 2 फरवरी 2026 के पूर्व का होना अनिवार्य है। उक्त अधिनियम के तहत अनुबंध की अवधि अधिकतम 5 वर्ष की होगी।

उन्होंने किसानों से अपील की है कि जिन्होंने सिकमी/ बटाईदार संबंधित कृषि भूमि में इस वर्ष गेहूं की फसल बोई है और समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करना चाहते हैं, तो उक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिशीघ्र निर्धारित प्रारूप में अनुबंध 3 प्रति में निष्पादित करना सुनिश्चित करें। विशेष उल्लेखनीय यह है कि 2 फरवरी 2026 की अवधि के बाद निष्पादन अनुबंध पर इस वर्ष समर्थन मूल्य में किसान पंजीयन एवं गेहूं विक्रय के लिए अनुबंध मान्य नहीं होगा।

अंत्योदय योजना में 35 किलोग्राम प्रति परिवार मिल रहा खाद्यान्न : गोविंद सिंह राजपूत

खाद्य मंत्री ने कहा, प्रत्येक पात्रता पर्चीधारी परिवार को राशन दुकान से मिल रहा खाद्यान्न

• साधना एक्सप्रेस, भोपाल

भोपाल । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत प्रदेश की लगभग 5.37 करोड़ अबादी को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो प्रति परिवार एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को 05 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न दिया जा रहा है। प्रत्येक पात्रता पर्चीधारी परिवार को राशन से दुकान से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

पात्र परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा 'वन नेशन वन राशन कार्ड' के तहत प्रदेश एवं देश की किसी भी

उचित मूल्य दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन/ओटीपी/नॉमनी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश के 15 लाख से अधिक पात्र परिवारों द्वारा पोर्टेबिलिटी से अपनी सुविधा अनुसार अन्य दुकान से प्रतिमाह राशन प्राप्त किया जा रहा है। पात्र परिवारों को पूरे माह उचित मूल्य दुकान से राशन का वितरण किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा पात्र परिवारों की पहचान सुनिश्चित करने एवं वास्तविक गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने तथा अपात्र / दोहरे हितग्राहियों को हटाकर नवीन हितग्राहियों को लाभांवित करने के लिये ई-केवाईसी करना अनिवार्य किया गया है। इसमें 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोडकर, पात्र हितग्राहियों के ई-केवाईसी उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन के साथ ही भारत सरकार के मेरा ई-केवाईसी मोबाईल एप के माध्यम से हितग्राही के फेस अथेंटिकेशन द्वारा किया जा सकता है।

29 पात्रता श्रेणी के नवीन हितग्राहियों को जोड़ने की कार्रवाई जारी :

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 29 पात्रता श्रेणी के अंतर्गत नवीन हितग्राहियों को जोड़ने की कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है। इन नवीन आवेदकों द्वारा पीओएस मशीन / फेस अथेंटिकेशन से ई-केवाईसी के बाद 3 दिवस की अवधि में पात्रता पर्ची जारी करने की व्यवस्था की गई है। विगत एक वर्ष में लगभग 20 लाख नवीन हिग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी की गई है। हितग्राही द्वारा ई-केवाईसी कराने के उपरांत पात्रता पर्ची जारी की जा रही है। किसी भी पात्रता पर्चीधारी परिवार का राशन रोकने की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिये गए हैं।

पात्रता पर्ची के लिये आवेदनकर्ताओं को ई-केवाईसी करने हेतु एसएमएस के साथ ही उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं एवं स्थानीय निकाय के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है।

मौसम ने बदली करवट किसानों के माथे पर चिंता की लकीर

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा I (राजेश नीरस) इन दोनों मौसम की बदलते मिजाज की स्थिति ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को भी बादल और सूर्य देव के बीच आंख मिचोली चलती रही, जिससे तापमान में नमी आई है। सुबह और रात्रि में ठंडक महसूस हो रही है, और लोग गरम वस्त्रों के बिना घर से नहीं निकल रहे हैं।

मौसम की स्थितिः - बादल और सूर्य देव की आंख मिचोलीः शनिवार को आकाश में बादल छाए रहे, जिससे तापमान में नमी आई।

- ठंडकः सुबह और रात्रि में

ठंडक महसूस हो रही है।

- मौसमी बीमारियों की आशंकाः मौसम की स्थिति के चलते मौसमी बीमारियों की आशंका बनी हुई है।

किसानों की चिंताः - फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर प्रभावः मौसम की अनिश्चितता से खड़ी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।

- बारिश और ओले गिरने की आशंकाः आकाश में बादल छाए रहने से बारिश और ओले गिरने की आशंका बनी हुई है, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है।

किसान अजय ममार का कहना है कि मौसम की स्थिति के चलते उनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि खेतों में चना, गेहूं, राहर, तू अर, मटर आदि की फसल खेतों में लेहलहा रही है।

भोपाल में दो दिवसीय वानिकी सम्मेलन शुरू, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आईएफएस मीट 2026 का उद्घाटन किया

• साधना एक्सप्रेस • भोपाल

भोपाल में दो दिवसीय वार्षिक वानिकी सम्मेलन और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) मीट 2026 का शुभारंभ 30 जनवरी 2026 को हुआ। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल और वन बल प्रमुख वी.एन. अम्बाडे भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए भारतीय वन सेवा के समर्पण और योगदान की सराहना की। उन्होंने मध्य प्रदेश के विशाल वन क्षेत्र और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन के कार्यों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने वन्यजीवों के संरक्षण में जल एवं जल संरचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया, और वन विभाग को इनके संरक्षण तथा विकास पर काम करने का निर्देश दिया।

पिछले दो वर्षों में डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व, रातापानी; माधव टाइगर रिजर्व, शिवपुरी; रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, नौरादेही; डॉ. भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, सागर; जहांनगढ़ अभयारण्य, श्योपुर; और ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व, बैतूल जैसे नए संरक्षित क्षेत्र विकसित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में जंगली भैंसा, एक सींग वाला भेड़ा और किंग कोबरा को बसाने के लिए भी आवास विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएफएस मीट भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय, संवाद और आत्मीयता को मजबूत करता है। यह जन सामान्य के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के मध्य प्रदेश शासन के संकल्प को क्रियान्वित करता है। उद्घाटन के अवसर पर वन विभाग के आईएफएस थीम गीत का विमोचन भी किया गया।

सम्मेलन में भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी डॉ. पी.बी. गंगोपाध्याय को वन संरक्षण क्षेत्र में उनके दीर्घकालीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके उपरांत भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में अधिकारियों एवं उनके परिजनों के लिए चित्रकला, प्रश्नोत्तरी और अन्य गतिविधियों के साथ एक संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

वानिकी सम्मेलन के दूसरे दिन का आयोजन मेनिट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स परिसर में किया गया। इस दौरान विभिन्न खेलों जैसे एरोबिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, पतंगबाजी, लेगन रेस, बोरा रेस, फॉग रेस, ट्रेजर हंट, बकेट वॉल, म्यूजिकल चेयर, गोरलैंड रेस और रस्साकशी का आयोजन किया गया।

छोटा जबलपुर में हुआ द्वितीय अनुभूति का चरण

गाडरवारा I (राजेश नीरस) विगत दिवस वन मंडल नरसिंहपुर अंतर्गत वन परिक्षेत्र गाडरवारा में वन संरक्षक सुश्री संध्या के दिशा निर्देश अनुसार वन मंडल अधिकारी सुश्री कल्पना तिवारी के मार्गदर्शन में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शासकीय पी ऍम श्री कन्या नवीन शाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाडरवारा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गाडरवारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदूखेड़ा के कुल 124छात्र-छात्राओं सहित 10 शिक्षक गण उपस्थित रहे कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान एवं सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ की इसके पश्चात सभी छात्र-छात्राओं को अनुभूति किट प्रदान किए गए तत्पश्चात अनुभूति प्रेरक संतोष

कौरव एवं अमन खरे वनरक्षक के द्वारा कैंप स्थल पर अनुभूति की संक्षिप्त जानकारी दी गई अनुभूति की थीम में भी बाघ, हम हैं बदलाव ,हम हैं धरती के दूत की जानकारी भी दी गई इसके पश्चात छात्र-छात्राओं को दो ग्रुप में बाटकर प्रकृति पथ पर वृक्षों झाड़ियां औषधीय पौधों वन्य प्राणियों की विस्टा पग मार्ग की पहचान एवं उनकी उपयोगिता महत्व तथा उनका संरक्षण संवर्धन की जानकारी दी गई दीमक की बामी ,पक्षी दर्शन ,सरीसृप आदि की जानकारी दी गई अनुभूति लोगों पर सामूहिक फोटोग्राफी लिया जाकर दोपहर भोजन उपरांत साहसिक गतिविधियां खाद्य श्रृंखला थैला निर्माण प्रश्नोत्तरी एवं मिशन लाइफ के सिद्धांतों से परिचित कराया वन विभाग की संरचना प्रमुख दायित्व एवं चुनौतियों से अवगत कराया तत्पश्चात पुरस्कार वितरण एवं शपथ ग्रहण सामूहिक गीत का आयोजन किया गया कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित उपवन मंडल अधिकारी गाडरवारा सुनील वर्मा , वन परिक्षेत्र अधिकारी गाडरवारा महेश कापुस्कर एवं जनप्रतिनिधि योगेश कौरव भाजपा जिला पंचायत सदस्य , विक्की गुप्ता समाजसेवी संगम राय सरपंच प्रतिनिधि गोटीटोरिया एवं अन्य गणमान्य नागरिको की उपस्थिति रही I

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, मिनाक्षी पांडेय द्वारा डीके ऑफसेट प्रिंटर्स 50/6 शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र से मुद्रित एवं 111/44, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र से प्रकाशित ।
संपादक मिनाक्षी पांडेय एवं स्थानीय संपादक मनीष पांडेय मो.न- 7566293490 मेल sadhnaexpress@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल म.प्र रहेगा ।)| RNI NO. MPHIN/2022/84698